শৰ্মা হাৰ্ডৱেৰ
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 12 | गुवाहाटी | बुधवार, 12 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

धर्म परिवर्तन और लैंड जिहाद रोकने को कानून बनाएगी प्रदेश सरकार : सीएम पेज 2

राहुल गांधी, पलायन मत कीजिए, बहस से मत डरिए : मंत्री हजारिका पेज 3

प्रशासन के आश्वासन पर अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन... पेज 5

हाकी विश्वकप में भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार पेज 7

अब वंदे *मातरम्* का अपमान होगा अपराध

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून हुआ लागू

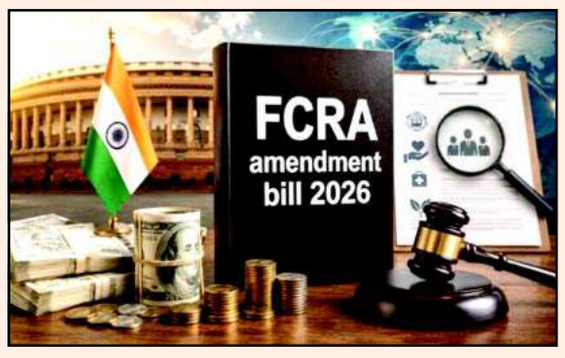

नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से *वंदे मातरम् बिल* को मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार, 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही, *राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026* अब कानून बन गया है। यह कानून वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान *जन गण मन* के बराबर का दर्जा देता है। राज्यसभा ने इस बिल को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। वहीं लोकसभा में यह बिल 30 जुलाई को पास हुआ था। अब राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह विधेयक, कानून बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इससे पहले, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम -शेष पृष्ठ दो पर

एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने की तैयारी, अल्पसंख्यक और ईसाई संगठनों में बढ़ी बेचैनी

नई दिल्ली। सरकार *विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026* को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि सरकार एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ बीजेडी समेत कुछ दल इसे संयुक्त समिति को भेजे जाने के पक्ष में हैं। विधेयक में एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में संबंधित संगठन की संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। विपक्ष का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों और ईसाई गैर सरकारी संगठनों की वैध विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानून किसी धर्म विशेष को लक्षित नहीं करता। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक के दौरान कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने एफसीआरए बिल का मुद्दा उठाया। हालांकि, यह बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। इन दलों ने सरकार से पूछा कि एफसीआरए बिल पर सदन में चर्चा कब होगी। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि सही समय आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस और टीएमसी ने विधेयक को वापस लेने की मांग की। वहीं, बीजेडी जैसे कुछ अन्य दलों का मानना है कि विधेयक को और गहन जांच-पड़ताल के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। -शेष पृष्ठ दो पर

अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, स्वयंसिद्ध और निर्विवाद वास्तविकता : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली (हि.स.)। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग बताते हुए इसे एक स्वयंसिद्ध और निर्विवाद वास्तविकता बताया है। यह बयान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नामों को मानकीकृत करने के भारत के हालिया कदम पर चीन की आपत्ति के जवाब में आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वयंसिद्ध है। साथ ही, मैं यह भी रेखांकित करना चाहता हूं कि इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। उल्लेखनीय है कि चीन अरुणाचल प्रदेश -शेष पृष्ठ दो पर

असम : नेशनल कराटे में गोल्ड जीतने वाली लड़की का परिवार टेंट में रहने को मजबूर

जोरहाट। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 17 वर्षीय जनमोनी कुंवर ने स्वर्ण पदक जीता है। सोमवार को जब वह अपने घर लौटीं, जहां उनका परिवार अभी भी टेंट में रह रहा है, क्योंकि पिछले महीने आई विनाशकारी बाढ़ में उनका घर बह गया था। जोरहाट जिले के भोगदोईपोरिया गांव की रहने वाली जनमोनी ने 7 से 9 अगस्त तक तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप की अशीहारा श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 19 जुलाई को इलाके में बाढ़ का पानी घुसने के बाद उनके परिवार को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके घर से करीब 150 मीटर दूर स्थित तटबंध टूट गया, जिससे गांव में पानी भर गया और परिवार की मछली पालन की जगह पूरी तरह तबाह हो गई। बत्तखें और मुर्गियां पानी में बह गईं, जबकि परिवार की भैंसों -शेष पृष्ठ दो पर

door graphy
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

जेपीएससी परीक्षा और दो बैकलॉग परीक्षाएं होंगी रद्द : सीएम

रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सदन में कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दो बैकलॉग जेपीएससी परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से कराई गई परीक्षा की जांच कराने की भी घोषणा की। छात्रों के आंदोलन और परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में चल रहे सियासी घमासान के बीच सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई। सीएम सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें *स्टूडेंट्स वॉइस विद स्टूडेंट्स* अभियान शुरू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से ज्यादा युवा साथियों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए -शेष पृष्ठ दो पर

लाल किले पर सुरक्षा का हाईटेक घेरा, इस बार एफआरएस-एएनपीआर से होगी निगरानी

नई दिल्ली। 15 अगस्त को लाल किले की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। लाल किले और आसपास के इलाकों में करीब 15 से 20 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी, जिसमें एफआरएस यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे भी शामिल हैं। हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में लाल किले के आसपास ऊंची इमारतों और अलग अलग जगहों पर मचान बनाकर स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। आसमान से आने वाले संभावित खतरे को देखते हुए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं, एएनपीआर यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से लाल किले और आसपास आने-जाने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं रहेगी। यमुना में पेट्रोलिंग के साथ-सा नदी किनारे के संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बलों की विशेष निगरानी रहेगी। होटल, गेस्ट हाउस की चेकिंग भी की जा रही है। यहां ठहरने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है।

– **आचार्य चाणक्य**

न्यूज गैलरी

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति समेत कई पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा

दमिश्क (हि.स.)। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को सत्ता से हटाए गए पूर्व शासक बशर अल-असद और कई पूर्व सैन्य एवं सुरक्षा अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपितों को जानबूझकर हत्या, यातना, मनमाने ढंग से हिरासत में रखने और मानवता के खिलाफ अपराधों -शेष पृष्ठ दो पर

होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का सौ प्रतिशत नियंत्रण : ट्रंप

वाशिंगटन (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस समय सिर्फ अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अभी होर्मुज जलडमरूमध्य पर केवल अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। हमारी नाकाबंदी अचूक है। यह फौलाद की दीवार की तरह है। इस जलडमरूमध्य पर हमारा 100 प्रतिशत नियंत्रण है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान लड़ाई में पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वह सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा। वहां महंगाई दर 300 प्रतिशत है। अमेरिका ने जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगों को हटा दिया है। -शेष पृष्ठ दो पर

सोनिया ने मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उन पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस सबके बावजूद इतिहास पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान के साथ याद करेगा। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल की आर्थिक नीतियों, सामाजिक योजनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल, आर्थिक नीतियों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उन्हें बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद उनके प्रधानमंत्री के रूप में किए गए कामों का रिकॉर्ड उनके पक्ष में है। डॉ. सिंह ने आर्थिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया और उनके कार्यकाल -शेष पृष्ठ दो पर

विस घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

राष्ट्रीय महामंत्री सहित 200 से अधिक कार्यकर्ता हिरासत में

रांची (हि.स.)। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुरानी विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। एबीवीपी -शेष पृष्ठ दो पर

पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से उन अपीलों के बारे में जानकारी मांगी, जिन पर शीर्ष अदालत द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल ने अब तक फैसला सुनाया है। इन ट्रिब्यूनल को उन लोगों की शिकायतों की सुनवाई का काम सौंपा गया है जिनके नाम पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के दौरान हटा दिए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी। मोहना की बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। चौधरी की याचिका के संबंध में चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि इसे 25 अगस्त को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें। चौधरी ने राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित एसआईआर से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे की मांग की थी। जस्टिस बागची ने कहा कि आपको हमें अब तक निपटाए गए मामलों की संख्या बतानी होगी, क्योंकि सिर्फ अपील दायर करना ही काफी नहीं है, हमें इन अपीलों के नतीजों के बारे में भी जानना है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने निपटाए -शेष पृष्ठ दो पर

सावन की अमावस्या पर लगेगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

रात होने के कारण भारत में नहीं दिखेगा

भोपाल (हि.स.)। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बुधवार, 12 अगस्त का दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय घटना होने जा रही है। बुधवार को भारत में जब लोग सावन की अमावस्या मना रहे होंगे, तब साल का सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में दिन के समय ही पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। मप्र की नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने मंगलवार को इस खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना विशेष रूप से यूरोप महाद्वीप के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि वहां पूरे 27 साल बाद कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देने जा रहा है। इससे पहले यूरोप ने साल 1999 में ऐसा नजारा देखा था। सारिका घारू ने बताया कि भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 बजे शुरू होगा और मध्य -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

जोरहाट में टूटे तटबंध के पांच में से चार हिस्सों की मरम्मत पूरी

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि जोरहाट में टूटे तटबंधों की मरम्मत का काम तेजी से दिन-रात जारी है। उन्होंने बताया कि ताजा जानकारी के अनुसार, कुल पांच स्थानों में से चार स्थानों पर तटबंध के टूटे हिस्सों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि शोलमारा में तटबंध की मरम्मत का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि शेष कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। उधर असम राइफल्स ने असम पुलिस और प्रादेशिक सेना के साथ संयुक्त अभियान में विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर असम के लेखापानी के जागुन क्षेत्र से एनएससीएन (केवाईए) के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने आज बताया कि अभियान के दौरान एक .32 कैलिबर पिस्तौल, एक मैगजीन और एक कैंपिंग टेंट बरामद किया गया। पकड़े गए कैडर और बरामद सामान को आगे की जांच एवं कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया।

धर्म परिवर्तन और लैंड जिहाद रोकने को कानून बनाएगी प्रदेश सरकार : सीएम

बांकुड़ा (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार जमीन की खरीद-बिक्री और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बांकुड़ा में आयोजित प्रशासनिक बैठक में कहा कि उनकी सरकार के सामने अब दो प्रमुख काम बाकी हैं— धर्म परिवर्तन और जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित कानून बनाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं और अब जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों को भी सख्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने ब्यौरा देते हुए कहा कि सीमा पर बीएसएफ को जमीन दे दी है। ओबीसी की अवैध सूची रद्द कर दी है। इमाम-मुअज्जिन भत्ता बंद कर दिया है। गोमाता का सम्मान सुरक्षित किया है। मुहर्रम हुआ, लेकिन तलवार निकालने की अनुमति नहीं दी। कुछ दिनों में यूसीसी आएगा। अब मेरे दो काम बाकी हैं। धर्म परिवर्तन और जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में कानून लाना। यह काम भी मैं कर रहा हूं। हालांकि, सरकार जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर किस तरह का कानून लाने जा रही है, इसका विस्तृत खाका मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं किया। माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धार्मिक आधार पर जमीन के हस्तांतरण और उससे जुड़े विवादों को नियंत्रित करना हो सकता है। इस तरह के कानून को लेकर असम का उदाहरण सामने आ रहा है। असम में जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित कुछ मामलों में सरकार की अनुमति और जांच की व्यवस्था लागू है। दूसरे धर्म के व्यक्ति को जमीन बेचने के मामलों में संबंधित प्रक्रिया, खरीदार की आय के स्रोत और स्थानीय सामाजिक प्रभाव जैसे पहलुओं की जांच किए जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। ओडिशा में भी जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर कुछ वर्गों और क्षेत्रों के लिए सख्त नियम लागू हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव और जमीन के स्वामित्व को लेकर भाजपा लंबे समय से *लैंड जिहाद* का मुद्दा उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि अवैध घुसपैठ और जमीन के हस्तांतरण के कारण कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है। इसी संदर्भ में प्रस्तावित कानून को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार भी असम की तर्ज पर जमीन की खरीद-बिक्री पर अतिरिक्त प्रतिबंध और सरकारी निगरानी की व्यवस्था लागू करेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद प्रस्तावित कानून का स्वरूप की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

देश की जनता व विपक्ष के सवालो का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी : बृजेन्द्र सिंह

रोहतक (हिंस)। पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने संसद के 22 दिन से चल रहे सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता व विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र-युवाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में इस मामले को लेकर सवाल पूछा, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंनें कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से हिली हुई है। उन्होंने सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार को संसद में इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह मंगलवार को रोहतक में अपने आवास स्थान नीली कोठी पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बृजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी दिन संसद में नहीं पहुंचे हैं और गृहमंत्री अमित शाह भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों पर पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भाजपा के विधायक नदारद दिखाई दिए, तो इसे गुटबाजी नहीं तो और क्या कहा जाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस में हाथ मिल रहे हैं, दिल मिले या न मिले, लेकिन भाजपा में तो हाथ भी नहीं मिल रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सद्भावना यात्रा के बाद अब जल्द ही पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में धन्यवाद दौरा शुरू किया जाएगा। इस दौरान यात्रा से जुड़े लोगों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया जाएगा। इसके बाद प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर लोगों से संपर्क साधा जाएगा, ताकि पार्टी के साथ नए लोगों को जोड़ा जा सके। बीस अगस्त को हिसार में कार्यक्रम भी होगा। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया के बयान पर भी पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी और जिस व्यक्ति से वह केवल एक बार मिले हैं, उसके बारे में जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी हुई तेज, बाजवा गुट ने राहुल गांधी से मांगा मुलाकात का समय

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी अब चरम पर पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तथा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बाद पार्टी में प्रताप सिंह बाजवा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 15 कांग्रेस विधायकों के साथ चंडीगढ़ में बैठक कर राहुल गांधी से मुलाकात करने का फैसला लिया। इसके बाद विधायकों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। विधायक पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात और नेताओं के बीच चल रहे विवाद को लेकर राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। इसी बीच प्रताप सिंह बाजवा भी दिल्ली पहुंचे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल 6 जुलाई को चंडीगढ़ पहुंचे थे। प्रताप सिंह बाजवा के सरकारी आवास पर जाकर उसके साथ मीटिंग की थी। भूपेश बघेल के कार्यक्रमों में खुलकर चन्नी समर्थकों ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ नारेबाजी की है। कई जगह तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत भी आई है। पार्टी अभी तक दो वरिष्ठ नेताओं की आपसी कलह को समाप्त नहीं कर सकी थी कि अब प्रताप बाजवा गुट भी सक्रिय हो गया है। खास बात यह है कि बाजवा के

हेमंत दत्ता की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक, अभिनेता और गीतकार हेमंत दत्ता की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि असमिया अभिनय और नाट्य जगत में हेमंत दत्ता द्वारा दिया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने इस विशेष दिन पर दिवंगत कलाकार को गहरी श्रद्धा के साथ याद किया।

योगी ने गोरखपुर में 70 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण

गोरखपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान मंगलवार को यहां 70 करोड़ की लागत से तैयार दो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने एनएच-24 सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग से ग्रीन सिटी कॉलोनी और पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक 2-लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज इस मार्ग के पूरा होने के अवसर पर क्षेत्र के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह लगभग दो किलोमीटर का मार्ग है। इससे आवागमन आसान हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत पहले से लोग रह रहे थे। उनके लिए आने-जाने में दिक्कत होती थी। सकरा मार्ग होने के नाते ट्रक, ट्राली आदि वाहन भी नहीं जा पाते थे। यहां पर कई स्कूल बने हैं। अब यहां के लोगों को दूर घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ जाने के लिए भी रास्ता आसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास के ढेर सारे कार्य गोरखपुर को नई पहचान दिला रहे हैं। आज फ्लाईओवर बन रहे हैं। बहुत से बनकर तैयार हो गए हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि आपका जीवन अच्छा हो।

पृष्ठ एक का शेष

अब वंदे मातरम् का ...

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गान (जन गण मन) को जानबूझकर गाने से रोकने या उसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालने पर रोक थी। वहीं राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था। राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते थे, जबकि दूसरी बार और उसके बाद हर बार दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की जेल का प्रविधान था। पुराने कानून में राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं था। बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते वक्त बताया गया, अभी वंदे मातरम के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई खास कानूनी प्रावधान नहीं है, जबकि इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर सम्मान दिया जाता है। वहीं अब किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने से जानबूझकर रोकने या उसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालने से रोकने के लिए, इस अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में लाया जा सके और ऐसे कामों को दंडनीय बनाया जा सके। बिल में आगे कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को कहा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम – जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी – को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी उसके बराबर होगा। इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजाए जाएं, तो वंदे मातरम के सभी छह पद पहले गाए जाने चाहिए। 28 जनवरी के एक आदेश में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया कि राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके छह पद गाए जाएंगे, जिनकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। आदेश में कहा गया कि जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जिस सभा में राष्ट्रगीत गाया जाए, वहां सभी लोग *अटेंशन* (सावधान) की मुद्रा में खड़े होंगे। कई निर्देशों वाले इस आदेश में कहा गया कि सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से होनी चाहिए।

एफसीआरए बिल को जेपीसी ...

सूत्रों के मुताबिक, डीएमके भी चाहती है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। यह विधेयक इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस) और विदेशी फंडिंग पर सरकार की निगरानी और नियंत्रण को और मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में बुधवार को लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी अथॉरिटी का गठन करना है, जो किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान की प्रक्रिया संभाल सके। एफसीआरए बिल का कड़ा विरोध कर रहे विपक्षी दलों का आरोप है कि इसके प्रावधान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। विपक्ष का कहना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान ईसाई एनजीओएस और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए मिलने वाली वैध विदेशी फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। सरकार के मुताबिक, विधेयक का उद्देश्य देश में आने वाले विदेशी योगदान को विनियमित करना और उससे जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करना है। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन सी. पी. राधाकृष्णन ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सदन के नेता जे. पी. नड्डा और विपक्ष के नेता जयराम रमेश (कांग्रेस) शामिल हुए। इनके अलावा तिरुचि शिवा (डीएमके) और सस्मित पात्रा (बीजेडी) ने भी बैठक में हिस्सा लिया। उधर विधेयक के प्रावधानों को लेकर ईसाई और अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल (जिसमें *काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम* के प्रतिनिधि शामिल थे) के साथ गृह मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय और धार्मिक चिंताएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि विधेयक को या तो वापस लिया जाए या फिर जेपीसी के पास भेजा जाए।

अरुणाचल भारत का अभिन्न ...

को दक्षिण तिब्बत या *जांगनान* का हिस्सा मानता है। वह 2017 से समय-समय पर वहां के स्थानों के नामों की सूचियां जारी करता रहा है। भारत इन दावों और नामकरण को वास्तविक स्थिति बदलने का प्रयास बताकर खारिज करता रहा है। अब भारत ने इन्हें मानकीकृत करने के लिए कदम उठाया है। वहीं, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामलों में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं और इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा मामलों की स्थिति व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को दर्शाएगी। इस बात को हाल ही में 6 अगस्त को आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक में भी दोहराया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने खुली और स्पष्ट चर्चा की और एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस बात पर सहमति बनी कि एलएसी पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए डब्ल्यूएमसीसी, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।

असम : नेशनल कराटे में ...

को किसी तरह सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह मछली पालन जनमोनी के चैंपियनशिप में भाग लेने से भी जुड़ा हुआ था। उनका परिवार लगभग तीन साल से मछलियां पाल रहा था और उन्होंने जनमोनी की दिल्ली यात्रा का खर्च उठाने के लिए इन्हें बेचने की योजना बनाई थी। जनमोनी के बड़े भाई कृष्णामोनी कुंवर ने कहा कि हमने मछलियां बेचकर जनमोनी को प्रतियोगिता में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन बाढ़ ने उस योजना को तबाह कर दिया। परिवार ने जनमोनी की कराटे प्रतियोगिताओं में भागीदारी का खर्च उठाने में मदद करने के लिए पहले अपनी दो भैंसें भी बेच दी थीं। जनमोनी ने महज पांच साल की उम्र में कराटे सीखना शुरू कर दिया था। सीमित प्रशिक्षण सुविधाओं के बावजूद, उन्होंने इस खेल को जारी रखा और 2023 में कांस्य व 2025 में स्वर्ण पदक जीता। वह इस साल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थीं, जब इलाके में बाढ़ आ गई। परिवार के विस्थापित होने और रेल सेवाएं प्रभावित होने के कारण, जनमोनी को दिल्ली भेजना एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे में असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आए एक कंपनी के संस्थापक को जनमोनी की स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके टीम के दिल्ली जाने, आने और रहने का खर्च उठाया। वहीं, जनमोनी के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। वहीं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने भी 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। मदद मिलने के बाद अंततः जनमोनी ने दिल्ली पहुंची और चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक के साथ वापस लौटीं। परिवार के तटबंध पर विस्थापित होने के बाद भी जनमोनी का प्रशिक्षण नहीं रुका। बिना किसी उचित प्रशिक्षण सुविधा के, उन्होंने अपना अभ्यास तब भी जारी रखा जब उनका परिवार अपने घर और आजीविका के नुकसान से जूझ रहा था। सोमवार को जनमोनी डिब्रूगढ़ हवाईअड्डे पर पहुंचीं और अपना मेडल लेकर सीधे अपने बाढ़ प्रभावित गांव की ओर लौट गईं। इस बीच, उनका परिवार अभी भी तटबंध पर ही रह रहा है। कृष्णामोनी के अनुसार, घर लौटने के बारे में सोचने से पहले उन्हें शायद नवंबर तक वहीं रहना पड़ सकता है। 12वीं कक्षा की छात्रा जनमोनी अब अपना कराटे करियर जारी रखना चाहती हैं। परिवार के लिए, उनकी बेटी का यह राष्ट्रीय स्वर्ण एक बेहद कठिन समय में आया है, जब वे बाढ़ की तबाही से उबरने की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं।

जेपीएससी परीक्षा और ...

अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए हैं। हमें ओएमआर से लेकर परीक्षा कैलेंडर, स्कोरकार्ड, प्रश्न-पत्र, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और जेपीएससी सहित दोनों आयोगों में संवैधानिक दायरे के भीतर जरूरी सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारा मकसद सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करना नहीं है। मौजूदा चुनौतियों का सामना करते हुए हम एक ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाना चाहते हैं जो आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह हो। इसलिए मैं झारखंड के अपने सभी युवा साथियों से एक बार फिर अपील करता हूं कि वो अपने सुझाव साझा करते रहें। आपका एक सुझाव न सिर्फ आज की परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगा, बल्कि झारखंड के हजारों-लाखों युवाओं का भविष्य संवारने में भी योगदान देगा। यह सुधार सिर्फ राज्य सरकार की कोशिश नहीं होगी। यह झारखंड के मेरे युवा साथियों की भागीदारी से होने वाला सुधार होगा। दरअसल, झारखंड में छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोपों के कारण पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जेपीएससी परीक्षा कैंसिल करने और मामले की सीबीआई से जांच कराने, परीक्षा में ज्यादा पारदर्शिता लाने और राज्य की परीक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं।

लाल किले पर सुरक्षा ...

का भी इस्तेमाल कर रही है। अभिज्ञान ऐप के जरिए संदिग्ध लोगों और अपराधियों से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड की जांच में मदद ली जा रही है। भीड़ के बीच किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान होने पर पुलिस तेजी से उसके बारे में जानकारी जुटा सकेगी। लाल किले और आसपास के इलाकों में पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। इन्हें नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वह कार्यक्रम के दौरान पतंग न उड़ाएं। हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस ने अलग से काइट कैचर्स को भी तैनात किया है यानी सुरक्षा एजेंसियां जमीन से लेकर आसमान तक हर संभावित खतरे पर नजर रखेंगी। लाल किले की चारदीवारी से लेकर आसपास के इलाकों, यमुना और खादर तक सुरक्षा का घेरा रहेगा। हजारों जवानों की तैनाती के साथ सीसीटीवी, एफआरएस (एफआरएस), एएनपीआर (एएनपीआर), एंटी-ड्रोन सिस्टम और अभिज्ञान ऐप जैसी तकनीक के जरिए 15 अगस्त के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। महात्मा गांधी मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग ,जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आउटर रिंग रोड, सलीमगढ़ फोर्ट के आसपास के सभी एरिया को सीसीटीवी कैमरे की जद में रखा गया है। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा के जरिए चुपके-चुपके पर नजर रखी जा रही है। लाल किला के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। लाल किले में कुछ जगह खासतौर पर ट्रिप वायर यानी तारे लगाई गई हैं, अगर कोई उनको पार करेगा तो भी पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही पीपल काउंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यानी जितने लोग लाल किले के अंदर पहुंचेंगे और जितने भी लोग बाहर निकलेंगे और बाकी लोग जो अंदर रह जाएंगे, उन सभी का एक-एक डाटा कंप्यूटर पर शो करेगा यानी कोई भी शख्स कार्यक्रम खत्म होने के बाद लाल किला परिसर में अंदर नहीं रह सकता। इसके अलावा एबंडेंट ऑब्जेक्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यानी अगर कोई शख्स अपना कोई सामान कहीं पर लावारिस छोड़ता है तो फौरन उसको भी पकड़ा जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ...

यह जलडमरूमध्य अब गैरईरानी जहाजों के लिए खुला है। नाकाबंदी के तहत जहाजों को ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अन्य शिपिंग जारी है। महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी नाकाबंदी पहली बार अप्रैल 2026 में लागू की गई थी। जून के मध्य में एक अंतरिम समझौते के तहत इसे अस्थायी रूप से हटा लिया गया। जहाजों पर हमलों के बाद जुलाई के मध्य में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी मध्य कमान ने इस क्षेत्र में 20 से अधिक युद्धपोतों को तैनात करने और अगस्त की शुरुआत तक दर्जनों वाणिज्यिक जहाजों (हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 55) का मार्ग बदलने की सूचना दी है। कमान ने कहा होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मार्ग बना हुआ है। ट्रंप की ताजा टिप्पणी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले समुद्री यातायात को लक्षित करने वाली अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच आई है। ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण को चुनौती दी है और इसे पूरी तरह से फिर से खोलने की शर्त रखी है।

सोनिया ने मनमोहन सिंह ...

में ऐसे कई फैसले लिए गए, जिनका असर लंबे समय तक रहा। उन्होंने डॉ. सिंह की तुलना उन नेताओं से भी की, जिनकी विरासत का मूल्यांकन तत्कालीन राजनीतिक विवादों के बजाय समय के साथ उनके काम के आधार पर किया जाता है। सोनिया ने लेख में 29 जुलाई 2026 को हुए एक घटनाक्रम का भी जिक्र किया, जब उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में अपनी टिप्पणियों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियां उस दौर की याद दिलाती हैं, जब डॉ. मनमोहन सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी तथा छवि को भी राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी ने कहा कि डॉ. सिंह की आर्थिक नीतियों का आकलन करते समय उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले के दौर को भी ध्यान में रखना चाहिए। साल 2004 में जब डॉ. सिंह प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के आर्थिक सुधारों के बाद तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेख में उन्होंने डॉ. सिंह की व्यक्तिगत कार्यशैली का भी उल्लेख किया और उन्हें शांत, विद्वान तथा सिद्धांतों पर कायम रहने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरोपों और आलोचनाओं के बावजूद डॉ. सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने डॉ. सिंह सरकार की कई प्रमुख योजनाओं और नीतिगत पहलों का जिक्र किया। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सूचना का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून और शिक्षा के अधिकार जैसे कदम शामिल हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि इन पहलों ने आम नागरिकों को अधिकार और सामाजिक सुरक्षा देने के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी को मजबूत किया। सोनिया गांधी ने डॉ. सिंह सरकार के दौरान सूचना के अधिकार को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ी और नागरिकों को सरकार से जवाब मांगने का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन का अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने डॉ. सिंह के कार्यकाल में शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े कदमों का भी उल्लेख किया। लेख में कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाना उस सरकार की सामाजिक नीतियों का हिस्सा था। सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में भी डॉ. सिंह के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उस दौरान संसद, मीडिया और नागरिक समाज को सरकार से सवाल करने और नीतियों पर बहस करने की पर्याप्त गुंजाइश थी। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह की विरासत का आकलन तत्कालीन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर नहीं, बल्कि उनके फैसलों, आर्थिक नीतियों और सामाजिक क्षेत्र में किए गए कामों के आधार पर किया जाना चाहिए। समय बीतने के साथ डॉ. सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में योगदान की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

विस घेराव के दौरान ...

के अनुसार, विधानसभा घेराव के दौरान संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह, झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी सहित 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया है। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर कथित लाठीचार्ज और हिरासत की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। एबीवीपी के झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने संदिग्ध परीक्षाओं को निरस्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा परीक्षा कराने तथा परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार की मांग की। प्रकाश टूटी ने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के जरिए दबाया नहीं जा सकता। एबीवीपी विद्यार्थियों के अधिकारों और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है और उनकी मांगों के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस ने पुरानी विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

चुनाव आयोग को नोटिस...

गए और अभी भी लंबित मामलों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी। चौधरी के वकील ने उन लोगों का मुद्दा उठाया जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और जिन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत मिलने वाले फायदों से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक उनकी अपीलों पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें ऐसे फायदों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, बेंच ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को पीडीएस के फायदे न मिलने की शिकायत के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की जा सकती है। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर आप अपनी याचिका का दायरा बढ़ाकर उसमें पीडीएस के मुद्दों को शामिल करते हैं, तो हम उस पर विचार नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हालांकि, अगर मामला अपीलीय ट्रिब्यूनल की निगरानी से संबंधित है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम हटाने को पीडीएस के फायदे न देने का आधार बना रही है, तो यह एक अलग मुद्दा है और इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य मुद्दा निपटाए गए मामलों की संख्या है, न कि वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाना या न हटाना। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से कहा कि आपको अपीलीय ट्रिब्यूनल के पूरे ढांचे पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसमें जजों तक ऑनलाइन पहुंच जैसी बातें शामिल हैं। ऐसे कई भविष्य-उन्मुख उपाय हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। हालांकि, मुख्य मुद्दा निपटाए जा रहे मामलों की संख्या है। हम नामों को हटाने या बनाए रखने पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सुलझाए गए मामलों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने बेंच से अनुरोध किया कि इस याचिका को 25 अगस्त को इसी तरह के अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए। चौधरी की याचिका के संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि इसे 25 अगस्त को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें। 10 मार्च को, कोर्ट ने स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश दिया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। ताकि उन लोगों की अपीलों पर सुनवाई की जा सके जिनके नाम पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की निचली अदालतों के जजों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी थी।

सावन की अमावस्या पर...

रात्रि को पार करते हुए मध्यरात्रि के बाद (13 अगस्त की) 01:27 बजे समाप्त होगा। चूंकि ग्रहण की पूरी अवधि भारत में रात के समय होगी, जब सूर्य पहले से ही क्षितिज के नीचे छिपा होगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। उन्होंने बताया कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा की विशाल छाया पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कवर करेगी।

राहुल गांधी, पलायन मत कीजिए, बहस से मत डरिए : मंत्री हजारिका

गुवाहाटी (हिंस)। झारखंड की राजधानी रांची में अपने न्यायोचित अधिकारों की मांग तथा झारखंड लोक सेवा परीक्षाओं में कथित व्यापक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित बर्बर पुलिसिया कार्रवाई की असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने कड़ी निंदा की। मंत्री पीयूष हजारिका ने मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे और निर्दोष छात्रों के विरुद्ध कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार द्वारा कथित रूप से की गई दमनात्मक एवं बलपूर्वक कार्रवाई ने देश की लोकतांत्रिक चेतना तथा मानवता की अंतरात्मा को भी शर्मसार किया है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के छात्र अपने भविष्य, अधिकारों तथा रोजगार के अवसरों के लिए अत्यंत शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और अनुशासित ढंग से आंदोलन कर रहे थे। रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मार्ग में कथित रूप से कंटीले तारों की बैरिकेडिंग किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रात के अंधेरे में भी उनका पीछा कर निर्ममता से लाठीचार्ज किया गया तथा निर्दयतापूर्वक वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित दृश्यों में कथित कार्रवाई के दौरान कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फटे हुए दिखाई दिए। इसके बावजूद, उन्होंने कहा, स्वयं को छात्रों के अधिकारों का प्रहरी बताने वाले तथाकथित छात्र नेता, स्वयंभू बुद्धिजीवी तथा राहुल गांधी, कथित रूप से प्रताड़ित छात्रों की करुण पुकार के प्रति आज पूरी तरह मौन हैं। हजारिका ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक परिस्थिति को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना तथा देश में अस्थिरता और अराजकता का वातावरण निर्मित करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड के युवाओं और छात्र समुदाय के साथ चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम सरकार को आंदोलनरत छात्रों की न्यायोचित मांगों का तत्काल समाधान करते हुए उन्हें पूरा करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि रांची में भर्ती संबंधी अनियमितताओं और कथित प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं युवाओं पर राहुल गांधी के निर्देश पर बर्बर अत्याचार किए जाने की सूचना भी सामने आई है। दिल्ली के जंतर-मंतर की घटनाओं पर राजनीति करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राहुल गांधी आज झारखंड के छात्रों की करुण पुकार के प्रति पूर्णतः बहरे क्यों हैं? उन्होंने प्रश्न किया कि दिल्ली में छात्रों के प्रति कथित कृत्रिम सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले राहुल गांधी को झारखंड जाकर कथित रूप से प्रताड़ित छात्रों की सुध लेने का समय क्यों नहीं मिला। मंत्री हजारिका ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के भविष्य की वास्तविक चिंता नहीं है और वे केवल सुविधावादी राजनीति करना चाहते हैं। जहां कांग्रेस की सरकारों में पुलिस द्वारा कथित रूप से दमन किया जाता है, वहां राहुल गांधी मौन धारण कर लेते हैं; और जहां उन्हें राजनीतिक लाभ की संभावना दिखाई देती है, वहां वे राजनीतिक नाट्य का मंचन करते हैं। मंत्री ने आगे सवाल किया कि अपने अधिकारों और भविष्य की मांग को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने वाले युवा समुदाय पर ऐसी निर्मम दमनात्मक कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने पूछा कि क्या छात्रों के प्रति कांग्रेस का समर्थन अब राजनीतिक सुविधा और कथित गुप्त राजनीतिक गणनाओं पर निर्भर करेगा? झारखंड के छात्रों के साथ कथित बर्बर व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करते हुए मंत्री हजारिका ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश के युवाओं से अपने पाखंडपूर्ण एवं दोहरे मापदंड वाली राजनीति के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी को देशवासियों के समक्ष जवाब देना ही होगा। पीयूष हजारिका ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी बार-बार कथित रूप से असत्यपूर्ण बयान देकर भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। मंत्री के अनुसार, उनका उद्देश्य न तो सार्थक संवाद है और न समाधान, बल्कि अराजकता उत्पन्न करना है; यही कारण है कि वे प्रतिदिन अपने दावों और उद्देश्यों को बदलते जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रारंभ में राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद उन्होंने संसद में नीट के विषय पर चर्चा की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने न केवल चर्चा के लिए तत्परता दिखाई, बल्कि प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कानून को भी और अधिक कठोर बनाया। इसके बाद राहुल गांधी ने जंतर-मंतर की घटना के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की। पीयूष हजारिका ने कहा कि सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था, *संसद को चलने दीजिए, गृह मंत्री सदन के पटल पर उत्तर देंगे*। किंतु, उन्होंने आरोप लगाया, विपक्ष ने जानबूझकर संसद को चलने नहीं दिया।

उर्वरक उपलब्धता और ऑयल पाम मिशन की कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने की समीक्षा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने मंगलवार को जनता भवन स्थित कार्यालय में दो समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। बैठकों में राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण तथा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम की प्रगति की समीक्षा की गई। उर्वरक उपलब्धता को लेकर हुई बैठक में मंत्री ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में असम में उर्वरक पहुंचाने वाले 12 रैक प्वाइंट की स्थिति की भी समीक्षा की गई। हजारिका ने उर्वरकों के परिवहन और वितरण को तेज एवं सुचारु बनाने के लिए रैक प्वाइंट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। मंत्री ने असम में कार्यरत सभी नौ उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और विशेष रूप से फसल के मौसम में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा अधिक कीमत वसूलने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए निगरानी मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में राज्य में स्थानीय स्तर पर उत्पादित उर्वरकों को प्राथमिकता देने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया, ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता बेहतर की जा सके। दूसरी बैठक में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के मासिक लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। हजारिका ने संबंधित कंपनियों को ऑयल पाम की खेती से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने और प्रदर्शन में सुधार करने का निर्देश दिया। राज्य के विभिन्न जिलों के जिला कृषि अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा किसानों को ऑयल पाम योजना के तहत उपलब्ध लाभ और सहायता के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया।

असम राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के लिए समर्पित मोबाइल एप लांच किया

गुवाहाटी (हिंस)। असम राज्य महिला आयोग ने मंगलवार को महिलाओं को अधिकार, कल्याण और शिकायतों से संबंधित जानकारी एवं सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपना समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया। गुवाहाटी स्थित असम राज्य महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा पर्यटन मंत्री अजंता नियोग ने मोबाइल एप का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश चंद्र साहू और असम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अंगूरलता डेका भी मौजूद रहीं। असम राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से यह मोबाइल एप विकसित किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और शिकायतों से संबंधित सहायता एवं सेवाओं तक सुविधाजनक, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। आयोग के अनुसार, मोबाइल एप के माध्यम से उसकी पहुंच और सेवाओं का विस्तार होगा तथा महिलाओं की शिकायतों के अधिक प्रभावी और समयबद्ध निवारण में मदद मिलेगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से यह पहल महिला सशक्तीकरण, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और राज्यभर में महिलाओं के लिए सुलभ सहायता तंत्र को और मजबूत करेगी।

बाढ़ से 10 जिलों की 126431 आबादी प्रभावित, 1 और शव मिला

गुवाहाटी (हिंस)। असम में अब भी बाढ़ से 10 जिलों की 126431 आबादी प्रभावित है। इस दौरान एक और शव मिला है। बाढ़ में सब कुछ गंवाने वाले लोग नये सिरे से अपने आशियाना बसाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। संपत्ति एवं आधारभूत ढांचे के नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है। गैर सरकारी संगठन और आम नागरिक प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सामग्री मुहैया करा रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से मदद तो नहीं कर सकते वो श्रमदान के जरिए इस आपदा से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऊपरी असम के शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट जिलों में लोगों का सामान्य जीवन अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 10 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार धनसिरि नदी (नुमलीगढ़ और गोलाघाट) तथा कुसियारा नदी (श्रीभूमि) इलाके में खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। इस बीच सोमवार को शिवसागर जिले में 1 और शव बरामद हुआ है। इस तरह बाढ़ से राज्य में मृतकों की कुल संख्या 102 पहुंच गई है। वर्तमान में बाढ़ की स्थिति कुल 10 जिलों में बनी हुई है। प्रभावित जिलों में नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरंग, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर, कछार, चराईदेव एवं जोरहाट शामिल हैं। बाढ़ से 10 जिलों के 25 राजस्व मंडलों के कुल 458 गांव प्रभावित हैं। वर्तमान समय में राज्य की कुल 126431 आबादी अभी भी प्रभावित हैं एवं 11287.04 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। बाढ़ में राहत एवं बचाव अभियान में एसडीआरएफ, सेना/अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एयर फोर्स, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस), सर्कल कार्यालय/स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा/प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में शनिवार को राज्य सरकार ने कुल 58 मेडिकल टीमों को तैनात किया। इस दौरान 4 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। इस बीच नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित 40 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावितों के बीच राज्य सरकार की ओर से चावल (क्विंटल में): 260.364, दाल (क्विंटल में): 46.548, नमक (क्विंटल में): 13.9728, मस्टर्ड ऑयल/सरसों का तेल (लीटर में): 725.27 के साथ पशुओं का चारा-गेंहूं का चोकर (क्विंटल में): 1396.07 राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

गुवाहाटी में 1.05 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस ने गुवाहाटी में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 21 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1.05 लाख रुपए मूल्य के 210 संदिग्ध जाली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवक की पहचान भरलुमुख निवासी हर्ष अग्रवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आज बताया कि पुलिस को आमबारी इलाके में जाली नोटों के प्रसार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अभियान चलाकर आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 500 रुपए मूल्य के 210 संदिग्ध जाली नोट बरामद किए। पुलिस के अनुसार, बरामद मुद्रा को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है। जांच अधिकारी अब जाली नोटों के स्रोत का पता लगाने के साथ-साथ इनके प्रसार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। आरोपित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गुवाहाटी में हाल के सप्ताहों के दौरान जाली मुद्रा के खिलाफ चलाए गए अभियान की कड़ी का हिस्सा है। इन अभियानों में कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के संदिग्ध जाली नोट बरामद किए जा चुके हैं। हाल ही के एक मामले में जीआरपी ने कामाख्या रेलवे स्टेशन से 7.37 लाख रुपए मूल्य के जाली नोट बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों की पहचान झारखंड के पाकुड़ जिले के निवासी 59 वर्षीय दयाल दास और 50 वर्षीय गुलाब शेख के रूप में हुई थी। दोनों को रात करीब 9.30 बजे प्लेटफॉर्म संख्या-1 से पकड़ा गया था। एक अन्य कार्रवाई में दिसपुर पुलिस ने छह माइल इलाके से 2.56 लाख रुपए मूल्य के संदिग्ध जाली नोट बरामद किए और कथित रूप से इनकी तस्करी में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया।

पशुपालन सेवाओं को मजबूत करने के लिए असम में मैत्रियों को कृत्रिम गर्भाधान उपकरण वितरित

गुवाहाटी (हिंस)। असम की पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री नीलिमा देवी ने मंगलवार को खानापारा स्थित क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पांच लाभार्थियों को प्रमाणपत्र तथा मैत्रियों को कृत्रिम गर्भाधान (एआई) संबंधी उपकरण वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य मैत्रियों को आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को उनके घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे राज्य में पशुओं के प्रजनन, उत्पादकता तथा पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव कैलाश चंद्र चमरिया और निदेशक डॉ. जयंत कुमार गोस्वामी भी उपस्थित रहे।

हर घर तिरंगा एवं *आजादी का अमृत महोत्सव* के तहत चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित

गुवाहाटी (हिंस)। *हर घर तिरंगा* अभियान एवं *आजादी का अमृत महोत्सव* के अंतर्गत आज गुवाहाटी के सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में लोखरा इलाके में ई समवाय द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा तिरंगे के प्रति सम्मान एवं जागरूकता की भावना को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ई समवाय के सहायक कमांडेंट/समवाय प्रभारी नवीन चंद द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं स्थानीय लोगों को *हर घर तिरंगा* अभियान के उद्देश्य तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

शिवसागर एवं चराईदेव जिलों में भाकिसं ने चलाया राहत, स्वच्छता एवं पुनर्वास अभियान

गुवाहाटी (हिंस)। उपरी असम के कई जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ से भारी जन-धन की हानि हुई है। खासकर शिवसागर एवं चराईदेव जिले में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने व्यापक स्तर पर जन-धन, कृषि एवं पशुधन को भारी क्षति पहुंचाई है। इस आपदा से 622 गांवों के लगभग 3.32 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें चराईदेव जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 1.42 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए, जबकि उसके बाद शिवसागर का स्थान है। बाढ़ के कारण लगभग 45,342 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई तथा 32,477 लोग विस्थापित होकर 81 सरकारी राहत शिविरों में शरण लेने को विवश हुए। इसके अतिरिक्त 74,000 से अधिक पशुओं की मृत्यु भी हुई है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारतीय किसान संघ (भाकिसं) पूर्ण समर्पण के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में निरंतर जुटा हुआ है। भारतीय किसान संघ के लखीमपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, धेमाजी, मोरीगांव, नलबाड़ी तथा कामरूप जिलों के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री के वितरण के साथ-साथ 1500 बीघा भूमि में रोपाई हेतु धान की पौध (पैडी सैपलिंग) की व्यवस्था की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए 5,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी वर्दी (स्कूल यूनिफॉर्म) उपलब्ध कराई जा रही है। भाकिसं से जुड़े तीन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीसी) ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान हेतु 3 लाख की राशि एकत्रित की है। जोरहाट जिला इकाई द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधों एवं घरेलू उपचारों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मोरीगांव जिले से 50 कार्यकर्ताओं की एक टीम पिछले चार दिनों से शिवसागर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण के साथ-साथ पीड़ितों परिवारों के घरों के पुनर्निर्माण, स्वच्छता अभियान तथा अन्य पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई है। बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए एक ट्रक पशु चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। बरपेटा एवं बंगाईगांव जिलों की इकाइयां बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु मशरूम उत्पादन, पशुपालन तथा अन्य आजीविका आधारित स्वरोजगार योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। जलस्तर कम होते ही कार्यकर्ता इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय होंगे। भाकिसं का लक्ष्य विभिन्न राहत, पुनर्वास एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 5,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचना तथा उन्हें पुन: आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करना है।

अनुभव बड़े टूर्नामेंट में काफी मदद करता है : दीपक गोहाई

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी रॉयल्स ने डिब्रूगढ़ वॉरियर्स को टूर्नामेंट में पहली हार सौंपकर इम्पीरियल ब्लू पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर असम प्रीमियर लीग (एपीएल) 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। टीम की इस जीत में पर्पल कैप धारक दीपक गोहाई ने गेंद से एक बार फिर अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ गुवाहाटी रॉयल्स के पांच मैचों में आठ अंक हो गए हैं। टीम ने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर डिब्रूगढ़ वॉरियर्स को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोनों टीमों ने अब तक चार-चार मुकाबले जीते हैं। गोहाई पांच मैचों में 12 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं। उनका इकॉनमी रेट 5.00 और गेंदबाजी औसत 8.33 है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/11 रहा है। अपने प्रदर्शन पर गोहाई ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में अनुभव मैच की परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार गेंदबाजी करने में काफी मदद करता है। उन्होंने कहा कि विकेट और बल्लेबाज के अनुसार गेंदबाजी में बदलाव करना टीम के लिए भी फायदेमंद होता है। डिब्रूगढ़ वॉरियर्स के खिलाफ जीत को खास बताते हुए गोहाई ने कहा कि टीम ने अपनी रणनीति को अच्छी तरह लागू किया और बुनियादी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि इस जीत से टीम का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा है। अपनी गेंदबाजी की सफलता के बारे में गोहाई ने कहा कि गति में बदलाव और सही लेंथ पर गेंदबाजी उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं देना भी उनके लिए लगातार कारगर साबित हुआ है। गोहाई ने टीम के प्रदर्शन का श्रेय शांत और सकारात्मक माहौल को दिया।

लोक भवन में केंद्र-प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने पर बैठक संपन्न

गुवाहाटी। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के निर्देश पर, आज यहां लोक भवन में असम के लिए गवर्नर के 19-सूत्रीय विकास एजेंडा और प्रधानमंत्री की प्रमुख, केंद्र-प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गवर्नर के कमिश्नर और सचिव श्री एस.एस. मीनाक्षी सुंदरम ने की। बैठक में असम सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में लगभग 39 विभागों और एजेंसियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान, कमिश्नर ने भाग लेने वाले विभागों और एजेंसियों को गवर्नर के 19-सूत्रीय विकास एजेंडा के बारे में जानकारी दी और इसके कार्यान्वयन के लिए एक व्यवस्थित, मापने योग्य और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक विभाग को राज्य की योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं (जिनमें प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाएं भी शामिल हैं) से संबंधित *मुख्य प्रदर्शन संकेतक* की पहचान करनी चाहिए और इन संकेतकों को गवर्नर के विकास एजेंडा के संबंधित बिंदुओं के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से प्रत्येक एजेंडा बिंदु के तहत प्रगति को स्पष्ट रूप से मापा जा सकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन लोगों के लिए ठोस और सार्थक परिणाम लाए। कमिश्नर और सचिव ने प्रतिभागियों को विकास एजेंडा के संबंधित बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभागों और एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली *मानक संचालन प्रक्रिया* के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में 19-सूत्रीय विकास एजेंडा और विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय, निरंतर निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर दिया गया।

रंगिया के बरमुरा खानापाड़ा नामघर में स्वास्थ्य जांच शिविर व वृक्षारोपण कार्यक्रम 16 को

रंगिया (विभास)। रंगिया सह-जिला के अंतर्गत बरमुरा खानापारा सुबुरी नामघर प्रांगण में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि आयोजन समिति के रजत जयंती वर्ष (रुपाली जयंती) समारोह और देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 16 अगस्त (रविवार) को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्षभर चलने वाले इन आयोजनों की चौथी कड़ी के तहत इस दिन विविध धार्मिक, सामाजिक व स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजन समिति के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी, जहां स्थानीय तथा आमंत्रित आयती नाम मंडलियों द्वारा *आयती नाम* (भक्ति संगीत) का सुरम्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसके उपरांत, सुबह 9 बजे स्वयंसेवी संस्था *समृद्धि* के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं, सुबह 10 बजे से नामघर प्रांगण में एक वृहद नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में *पैथकाइंड लैब* के सौजन्य से मरीजों को नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श देने के साथ-साथ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नि:शुल्क जांच उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, अन्य विभिन्न प्रकार की रक्त जांचों पर भी विशेष और आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी। आयोजन समिति ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं व नागरिकों से इन सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया है।

एसएसबी, रानीघुली ने निकाली हाफ मैराथन, गूंजा *हर घर तिरंगा* का संदेश

कोकराझाड़ (विभास)। *हर घर तिरंगा* अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 11 अगस्त 2026 को छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), रानीघुली द्वारा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की अलख जगाते हुए एक भव्य हाफ मैराथन दौड़ एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रेरणादायक आयोजन कमांडेंट श्री रविंदर कुमार के मार्गदर्शन और द्वितीय कमान अधिकारी मनोज संवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। एसएसबी के जवानों और सीमावर्ती क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों ने भारी उत्साह के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा व सम्मान बनाए रखने की अपील की गई। मैराथन के माध्यम से एसएसबी के जवानों ने *हर घर तिरंगा* का संदेश घर-घर तक पहुंचाया। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई। इस आयोजन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और राष्ट्रभक्ति के बंधन को और अधिक प्रगाढ़ किया है। छठी वाहिनी एसएसबी के इस प्रयास से क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना, गौरव और उत्साह का अनूठा माहौल देखने को मिला।

संपादकीय

संसद चलेगी या पटाक्षेप

संसद के मानसून सत्र के सिर्फ चार दिन शेष हैं। इनमें सोमवार भी शामिल है। हम यह संपादकीय संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लिख रहे हैं, लिहाजा सोमवार को सदन में क्या हुआ, उसका विश्लेषण बाद में ही कर सकते हैं। सरकार ने एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) संशोधन बिल पेश और पारित करना तय किया था, लेकिन विपक्ष का विरोध था। परिसीमन बिल इस सत्र में लटकता दिख रहा है। यदि परिसीमन बिल पारित नहीं होगा, तो महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन कानून) 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। संशोधन बिल पारित कराने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस के 20, शिवसेना (उद्धव) के 6 लोकसभा सांसद और 'आप' के 7 राज्यसभा सांसद तोड़े गए थे। एनसीपी (शरद) के 8 लोकसभा सांसदों पर भी सरकार की निगाहें हैं। इन सांसदों ने सोमवार, 10 अगस्त, को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और स्वादिष्ट व्यंजन भी चखे। शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने भी परिसीमन बिल को समर्थन का बयान दिया है, लिहाजा उसकी एकमात्र लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल के वोट का भी जुगाड़ हो गया है। द्रमुक के 22 सांसद भी सरकार के पाले में आ सकते हैं, फिलहाल कुछ शर्तों पर 'सौदेबाजी' जारी है। यदि इन सभी पालाबदलू सांसदों का भी समर्थन मिल जाता है, तो भी सरकार 360 के आंकड़े तक नहीं पहुंचती। लोकसभा में यह दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा है। सरकार और आंध्रप्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस के दरमियान भी पालाबदल या घोषित समर्थन की बातचीत जारी है। यदि लोकसभा सीटों के नए परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू करना था, तो 2023 में लगभग सर्वसम्मति से यह बिल पारित क्यों किया गया? कानून बनने के बावजूद करीब 3 साल तक उसकी सरकारी अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई? मौजूदा संदर्भ में अभी तो जनगणना जारी है, जो 2027 में संपन्न होगी। 2011 अथवा 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना बेमानी है, क्योंकि जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है और लोकसभा सीटें बेहद असंतुलित हैं। बहरहाल हमारा सवाल है कि शेष चार दिनों में भी संसद चलेगी या यूं ही उसका पटाक्षेप करना पड़ेगा। अभी तक संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की 'बलि' चढ़ती रही है। देश के करदाताओं के 100 करोड़ रुपए से अधिक पर पानी फिर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपनी जिद पर अड़े हैं और कमोबेश कांग्रेस भी अड़ी है कि गृहमंत्री सदन में आएं और छात्रों, युवाओं पर बर्बर प्रहारों का जवाब दें। बीते 13-14 दिनों से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन में दिखाई नहीं दिए। यह दुर्लभ और अप्रत्याशित हकीकत है। वे संसद के प्रति जवाबदेह हैं! अच्छा होता कि गृहमंत्री कमोबेश लोकसभा में आते और विपक्ष के शोर-शराबे में ही ऐसा जवाब देते कि विपक्ष कांप उठता! वैसे हमने किसी भी गृहमंत्री के जवाब पर किसी भी विपक्ष को कांपते हुए, कभी भी, नहीं देखा। गृहमंत्री प्रधानमंत्री से प्रेरणा ले सकते थे, जिन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उठाए गए तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोलते रहे। संसद के भीतर का वह भी दुर्लभ और असंसदीय अवसर था, क्योंकि व्यवस्था और परंपरा यह रही है कि जब प्रधानमंत्री एवं सदन के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो हंगामा मौन हो जाता है। सभी सदन के नेता की बात सुनते हैं। यह संसदीय परंपरा भी ढह गई है। बहरहाल मानसून सत्र में एंटी पेपरलीक बिल का उदाहरण दिया जा सकता है, जिस पर दो दिनों में घंटों चर्चा हुई और बिल ध्वनि-मत से पारित किया गया। विपक्ष के एक भी सांसद ने शिक्षा-सुधार, परीक्षा-सुधार और समग्रतः शिक्षा-व्यवस्था पर कोई भी सुझाव नहीं दिया। बस, सत्ता-पक्ष को कोसते रहे और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहे। शेष बिल ऐसे थे, जो कभी भी पारित किए जा सकते थे। वे भी सदन में 'हां' या 'ना' के शोर के साथ पारित किए गए। कोई बहस नहीं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारी संसद की कार्यवाही बाधित रहती है, सिर्फ विधायी पेपर और रपटें सदन के पटल पर रखी जाती हैं और फिर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है।

सरकार ने एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) संशोधन बिल पेश और पारित करना तय किया था, लेकिन विपक्ष का विरोध था। परिसीमन बिल इस सत्र में लटकता दिख रहा है। यदि परिसीमन बिल पारित नहीं होगा, तो महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन कानून) 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। संशोधन बिल पारित कराने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस के 20, शिवसेना (उद्धव) के 6 लोकसभा सांसद और 'आप' के 7 राज्यसभा सांसद तोड़े गए थे। एनसीपी (शरद) के 8 लोकसभा सांसदों पर भी सरकार की निगाहें हैं। इन सांसदों ने सोमवार, 10 अगस्त, को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और स्वादिष्ट व्यंजन भी चखे। शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने भी परिसीमन बिल को समर्थन का बयान दिया है, लिहाजा उसकी एकमात्र लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल के वोट का भी जुगाड़ हो गया है। द्रमुक के 22 सांसद भी सरकार के पाले में आ सकते हैं, फिलहाल कुछ शर्तों पर 'सौदेबाजी' जारी है।

कुछ अलग

पूर्णता, दरार और मनुष्य

पृथ्वी ने पहली बार गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि पर्वतों ने उसे अपने भीतर तक महसूस किया। नदियों ने अपने स्वर में थोड़ा बदलाव किया। हवा कुछ अधिक हल्की हो गई। और काल... पहली बार मुस्करा उठा। उसे लगा- आज सृष्टि ने अपनी पहली भूल नहीं, अपना पहला सत्य स्वीकार किया है। उस दिन से दरार केवल पत्थरों में नहीं रही। दरार प्रकृति के स्वभाव में बस गई। जहां बीज फूटा, वहां एक दरार थी। जहां अंडे का कवच टूटा, वहां भी एक दरार थी। जहां शिशु ने पहली सांस ली, वहां भी एक अदृश्य दरार खुली। जहां किसी नए विचार ने किसी पुराने विश्वास को तोड़ा, वहां भी एक अदृश्य दरार जन्मी। काल आंखें मूंदकर यह सब देखता रहा। उसने भीतर तक कुछ महसूस किया। फिर अपनी अदृश्य पुस्तक में एक वाक्य लिखा, 'पूर्णता स्थिरता देती है, दरार जीवन देती है।' धीरे-धीरे यह बात स्वयं पृथ्वी भी समझ गई। उसे अनुभव हुआ कि जो पूरी तरह बंद है, वह सुरक्षित तो हो सकता है, जिंदा नहीं। जो बीज कभी नहीं फूटता, वह अंततः सड़ जाता है। जो घर कभी नहीं खुलता, वह घुटन से भर जाता है। जो समाज परिवर्तन नहीं स्वीकारता, वह कठोर हो जाता है। और जो विचार प्रश्नों के लिए बंद हो जाए, वह अंधविश्वास बन जाता है। इसलिए प्रकृति ने दरारों को कभी शत्रु नहीं माना। वे उसके लिए परिवर्तन की सांस थीं। जीवन की खिड़कियां थीं, दरीचे थे। काल की लिखावट थीं। युगांतर में मनुष्य ने दरार को दोष कहा। राजमिस्त्री ने उसे निर्माण की त्रुटि कहा। शासकों ने उसे व्यवस्था का संकट बताया। फलफसियों ने जीवन का दर्शन। इतिहासकारों ने उसे सभ्यताओं के पतन का संकेत माना।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष

युवा शक्ति को मिले दिशा, सपनों को मिले उड़ान

युवा केवल उम्र की एक अवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा, साहस, कल्पना, परिवर्तन और नवसृजन की चेतना का नाम है। जिस समाज की युवा शक्ति जाग्रत, संवेदनशील और रचनात्मक होती है, वह समाज परिवर्तन की नई इबारत लिखता है। इसके विपरीत जब युवा ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है तो वही शक्ति हिंसा, नशे, उग्रवाद, अपराध, निराशा और विध्वंस का कारण बन सकती है। इसलिए, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि युवा क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि उनकी विराट ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जा रहा है। इसी चिंतन को वैश्विक स्तर पर महत्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। वर्ष 2000 से इस दिवस का आयोजन शुरू हुआ। इस वर्ष का विषय है- 'विभिन्न परिस्थितियाँ, साझा आकांक्षाएँ।' यह विषय आज की युवा पीढ़ी की वास्तविकता को बहुत गहराई से अभिव्यक्त करता है। दुनिया के युवाओं की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कहीं गरीबी और बेरोजगारी है, कहीं युद्ध और असुरक्षा, कहीं शिक्षा के अवसरों की कमी है, कहीं तकनीकी असमानता और पर्यावरण संकट है, लेकिन इन सबके बीच उनकी आकांक्षाएँ आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। वे सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्थक रोजगार, सुरक्षा, मानसिक सुख-शांति, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर भविष्य चाहते हैं। दुनिया की सरकारों को यह समझना होगा कि युवा केवल चुनाव के समय याद आने वाला मतदाता नहीं हैं। वह राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। जिस युवा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिये जाते हैं, उसकी आवाज उन निर्णयों में कितनी शामिल है, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण पैमाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 युवाओं को शांति निर्माण और हिंसा की रोकथाम में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि युवा समस्या नहीं, बल्कि समाधान की शक्ति हैं। आज आवश्यकता है कि हर देश में ऐसी प्रभावी व्यवस्था बने, जिसमें विद्यार्थी, उद्यमी, किसान, वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता युवा सीधे नीति-निर्माताओं से संवाद कर सकें। केवल युवाओं पर योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के साथ योजनाएँ बनाना आवश्यक है। भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में उसकी युवा आबादी भी है। भारत के युवाओं ने अनेक बार सिद्ध किया है कि उनमें केवल नौकरी पाने की आकांक्षा नहीं, बल्कि कुछ नया करने की बेचैनी भी है। विज्ञान, खेल, तकनीक, उद्यमिता, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा से लेकर अनेक क्षेत्रों में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भारत के पुनर्निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। उनका विश्वास था कि जाग्रत, चरित्रवान और संकल्पवान युवा राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी युवाओं के सपनों को भारत के

सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्थक रोजगार, सुरक्षा, मानसिक सुख-शांति, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर भविष्य चाहते हैं। दुनिया की सरकारों को यह समझना होगा कि युवा केवल चुनाव के समय याद आने वाला मतदाता नहीं है। वह राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। जिस युवा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिये जाते हैं, उसकी आवाज उन निर्णयों में कितनी शामिल है, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण पैमाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 युवाओं को शांति निर्माण और हिंसा की रोकथाम में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि युवा समस्या नहीं, बल्कि समाधान की शक्ति है।

भविष्य से जोड़ा। उनके चिंतन का मूल संदेश था कि बड़े सपने देखो, ज्ञान अर्जित करो और उन सपनों को कर्म में बदलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत के विकास विमर्श में युवा शक्ति, नवाचार, कौशल, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अब अगला चरण इससे आगे जाने का है। युवा को योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का सह-निर्माता बनाना होगा। युवा दिवस की सार्थकता तब होगी जब 12 अगस्त के बाद भी युवा के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। क्यों न इस वर्ष प्रत्येक शहर में युवा स्वप्न संवाद आयोजित हों, जिसमें युवा लिखें कि वे अपने देश को अगले दस वर्षों में कैसा देखना चाहते हैं। उन सपनों को केवल कागज पर न रखा जाए, बल्कि सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर उनमें से व्यवहारिक योजनाओं को धरातल पर उतारें। प्रत्येक युवा कोई एक उपयोगी कौशल सीखे और समाज के लिए कोई एक जिम्मेदारी स्वीकार करे। प्रत्येक जिले में ऐसे युवा नवाचार केंद्र स्थापित हों, जहाँ स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए युवा अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का उपयोग कर सकें। आज युवा शक्ति के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में नशा, डिजिटल लत, हिंसक प्रवृत्तियाँ, मानसिक तनाव, बेरोजगारी और उद्देश्यहीनता हैं। नशे का फैलता जाल केवल व्यक्ति को नहीं, परिवार और राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को भी कमजोर करता है। युवाओं को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि नशा मत करो, बल्कि उन्हें जीवन का ऐसा उद्देश्य देना होगा कि नशे की आवश्यकता ही महसूस न हो। खेल, योग, ध्यान, कला, साहित्य, सेवा, उद्यमिता और सामाजिक गतिविधियों से युवाओं को जोड़ना होगा। खाली समय को रचनात्मक समय में बदलना नशामुक्ति की सबसे प्रभावी सामाजिक रणनीति हो सकती है। आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद की कमी भी एक चुनौती है। बुजुर्ग अनुभव के प्रतीक हैं और युवा ऊर्जा के। अनुभव यदि ऊर्जा से नहीं जुड़ेगा तो वह जड़ हो सकता है और ऊर्जा यदि अनुभव से नहीं जुड़ेगी तो दिशाहीन हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है अंतरपीढ़ी संवाद की। परिवारों, संस्थाओं और सरकारों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें युवा नई सोच प्रस्तुत करें और वरिष्ठ पीढ़ी अपने अनुभव से उनका मार्गदर्शन करे। अनुभव और ऊर्जा का यह समन्वय राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकता है। आज दुनिया के अनेक हिस्सों में युवा आंदोलन हो रहे हैं। युवाओं की आवाज सत्ता और व्यवस्था तक पहुँच रही है। भारत में भी समय-समय पर युवाओं ने अपनी आकांक्षाओं और असंतोष को आंदोलन का रूप दिया है। लेकिन युवा आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब वह केवल विरोध की आवाज न रहकर विकल्प की आवाज बने। युवा कहे कि हमें केवल शिकायत नहीं करनी, समाधान भी देना है। हमें केवल रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार सृजित करने की क्षमता भी चाहिए। हमें केवल अधिकार नहीं चाहिए, हम जिम्मेदारियाँ भी निभाएँगे। हम केवल सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने आए हैं। यही युवा आंदोलन की नई परिभाषा हो सकती है। यौवन अपने आप में उपलब्धि नहीं है। युवकत्व चेतना की अवस्था है। चेहरे पर जवानी हो और विचारों में जड़ता हो तो यौवन अधूरा है। ऊर्जा हो लेकिन दिशा न हो तो वही ऊर्जा संकट बन सकती है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को दो चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है-जोश और होश। जोश उसे ऊँचा उड़ाए और होश उसे सही दिशा दे। जोश उसे सपने दिखाए और विवेक उन सपनों को यथार्थ में बदले। जोश उसे संघर्ष करना सिखाए और करुणा उसे मनुष्य से जोड़े। स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणा, सुकरात की प्रश्नाकुलता, महात्मा गांधी की करुणा और डॉ. कलाम के सपनों का समन्वय आज के युवा के व्यक्तित्व में होना चाहिए। दुनिया के युवाओं से यह कहना आसान है कि बड़े सपने देखो, लेकिन केवल सपने देखने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। सपनों को आकार देने के लिए अवसरों की संरचना भी करनी होगी।अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विषय हमें एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है कि हमारी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएँ साझा हैं। भारत का युवा अवसर चाहता है, अफ्रीका का युवा शिक्षा और रोजगार चाहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र का युवा शांति चाहता है, द्वीपीय देशों का युवा सुरक्षित पर्यावरण चाहता है और तकनीकी दुनिया का युवा समान अवसर चाहता है। अर्थात दुनिया के युवा अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग संस्कृतियों में रहते हैं, लेकिन उनके सपनों की भाषा बहुत कुछ समान है। इसलिए आज दुनिया को युवा शक्ति को नियंत्रित करने से अधिक उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम केवल युवाओं को बधाई न दें, बल्कि उन्हें अवसर दें-अपनी बात कहने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, निर्णय लेने का और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का। सरकारें युवाओं की सुनें, परिवार उनके सपनों को समझें, शिक्षण संस्थान उनकी प्रतिभा को पहचानें, समाज उनके प्रयोगों को अवसर दे और युवा स्वयं अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानें।

देश दुनीया से

आंकड़ों की बाजीगरी और यथार्थ की अनदेखी

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण सर्वे का उद्देश्य देश में प्रजनन दर, मृत्यु दर, परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर आवश्यक आंकड़े प्रदान करना है। यह सर्वे हर पांच साल में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में उभरती चुनौतियों को दर्शाते हुए भविष्य के नीति निर्धारण को डेटा-बेस्ड व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसके चक्र-6 के आंकड़े हाल ही में मई में प्रकाशित किए गए। उल्लेखनीय है कि यह सर्वे ही भविष्य के नीति निर्धारण का आधार बनता है। इसके बिना नागरिक तथा नीति-निर्धारक आदि सरकार की नीतियों का विश्लेषण आंकड़ों की बजाय सरकारी आख्यानों के आधार पर करने को मजबूर होते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को जारी करने में जान-बूझकर विलंब तथा अनावश्यक हस्तक्षेप के जरिए सरकार ने इसकी नीतियों के सर्वे-आधारित विश्लेषण के आधार को ही छीन लिया। एनएफएचएस-5 (2019 से 2021) व इससे पहले के सर्वे चक्र में 131 प्रमुख संकेतकों की स्थिति दिखाई जाती रही। ताजा सर्वे में केवल 101 संकेतकों की स्थिति ही दर्शाई गई है। इस तरह कुछ प्रमुख संकेतकों को नजरअंदाज कर दिया गया है; जैसे- खून की कमी की व्याप्ति, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता तथा आबादी, जन्म के समय लिंगानुपात, रसोई के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच, सैनिटाइजेशन कवरेज, एचआईवी व कैंसर संबंधी जांच आदि। इस तरह से उन सभी संकेतकों को लगभग निकाल दिया गया, जिन पर सरकार का प्रदर्शन सबसे कमजोर था। यह बहु-प्रचारित योजनाओं की जांच-परख से बचने और छांट-छांट कर गरीबी, शिशु पोषण और महिला स्वास्थ्य की विफलताओं पर पर्दा डालने का मसला भी है। व्यापक स्तर पर यह इस तथ्य को छिपाने की ही कोशिश है कि बाजार सुधार के नाम पर चलाई जा रही नीतियों से हम राष्ट्र के तौर पर निर्धनतम तबकों जैसे महिलाएं, बच्चे और गरीबों की कीमत पर निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य उद्योग को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। एनएफएचएस-6 में केवल पहले से चले आ रहे संकट को हटाया ही नहीं, बल्कि

विकृत स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के रुझानों को पोषित करने के लिए कुछ नए संकेतक तक भी जोड़ दिए गए हैं। इनका जोर अल्पपोषण की बजाय जीवनशैलीगत संकेतकों की तरफ ज्यादा है, मसलन-मोटापा। याद रहे, दक्षिण एशिया में गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों की आधी संख्या भारत में होती है। फिर भी, नीतिगत प्राथमिकताओं का अल्पपोषण से मोटापे की तरफ मोड़ना एक खास दृष्टिकोण का संकेतक है। हमारे यहां 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन 29.3 प्रतिशत पर है, दुबलापन 31.8 प्रतिशत, अल्प विकास 19.0 प्रतिशत तथा अत्यधिक अल्प विकास 5.02 प्रतिशत पर है। देश में 6 से 23 महीने के बच्चों में केवल 15.3 प्रतिशत को ही पर्याप्त खुराक मिल पाती है। स्तनपान से पोषण 63.7 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत पर आ गया है। मोटे तौर पर हर पांच में से एक स्त्री-पुरुष अब भी दुबला या अंडरवेट है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस स्थिति को महामारिगत ध्रुवीकरण कहते हैं, जहां किसी आबादी के बीच स्वास्थ्य संबंधी नतीजे समूहों के बीच बढ़ते पैमाने पर विभाजित होते जाते हैं। इसमें रुग्णता, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य रक्षा तक पहुंच के संबंध में समूहों के बीच खाई बढ़ती जाती है। रक्त अल्पता के आंकड़ों को हटाकर मोटापे के आंकड़े को जोड़ना स्वास्थ्य स्थिति की अधूरी तस्वीर ही सामने लाता है, जिसमें पोषणगत बुनियादी विफलताओं को किनारे किया जाता है। सबसे नाटकीय ढंग से रक्ताल्पता के आंकड़ों को नजरअंदाज किया गया है। एनएफएचएस-5 में संकट बढ़ने की जानकारी सामने आई थी। 5 साल से कम आयु के बच्चों में खून की कमी 58.6 प्रतिशत से बढ़कर 67.1 प्रतिशत हो गई थी और 15 से 49 वर्ष आयु तक की महिलाओं के बीच यह 57 प्रतिशत थी, जिससे 'रक्ताल्पता मुक्त भारत योजना' पर सवाल उठे थे। इसी प्रकार, जन्म के समय लिंगानुपात हटा दिया गया है, जबकि यह लैंगिक भेदभाव का सबसे सशक्त संकेतक माना जाता है। एक स्वास्थ्य सर्वे जवाबदेही का औजार भी है। इसमें से सरकार की नीतियों की विफलताएं सामने लाने वाले संकेतकों को हटा देना गंभीर मसला है। हटाए जाने का पैटर्न भी अपनी कहानी कहता है। मिसाल के तौर पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में गरीब महिलाओं को रसोई के कनेक्शन मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई थी। एनएफएचएस-5 में पता चला था कि 40 प्रतिशत परिवारों को अब भी ईंधन के लिए चूल्हा फूंकना पड़ता है। अब एनएफएचएस-6 से इसे हटा दिया गया है। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन में 10 करोड़ शौचालय बनवाने के बाद 2019 में सरकार ने भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। इसके बावजूद एनएफएचएस-5 में पता चला था कि 19 प्रतिशत परिवारों को शौचालय की सुविधा मिली ही नहीं थी। उसे भी चक्र-6 में हटा दिया गया है। स्त्री व पुरुष नलबंदी में 70:1 का भारी अंतर दशकों से जस का तस बना हुआ है। बताया जाता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक, प्रो. के.एस. जेम्स की देखरेख में पेश किए जा रहे कुछ आंकड़ों से सरकार नाखुश थी। जेम्स ने इन आंकड़ों को हटाने से मना कर दिया था और उन्हें निलंबित कर दिया गया। सार्वजनिक आलोचना के बाद उनका निलंबन वापस लेकर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया।

आप का नजरीया

मानसून के कितने प्रश्न

बरसात में टपकती छतों, टूटती सडक़ों, उखड़ती जलपरियोजनाओं और उखड़ते बिजली के खंभों के हजारों दोष अगर विधानसभा का मानसून सत्र जानता है, तो तमाम विधायकों को शत शत प्रणाम, वरना अब तक विधानसभा पहुंचे करीब पांच सौ प्रश्नों में हम किसमें अपना भविष्य खोजें। प्रश्न जनता की कचहरी से उठकर विधानसभा के कक्ष में उद्गार बनें, तो प्रदेश की असली सत्ता हितमतगार बनेगी। ये प्रश्न बाहें फैलाए हर बार विधानसभा के सत्रों से पूछते हैं कि फलां सडक़ पर गड्ढे क्यों हैं या ढह गई पुलिया पर दोबारा काम क्यों नहीं हुआ। अगर हम सडक़ दुर्घटनाओं में मारे गए सैकड़ों लोगों का वृत्तांत सुन लें, तो सत्र की चर्चा में सडक़, परिवहन, वाहन सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर विश£षण कर पाएंगे। अगर चिट्टे पर चर्चा करेंगे, तो शिक्षा की जरूरतों, अभिभावकों की मन्नतों और कानून-व्यवस्था के अमल पर संवेदनशील होंगे। क्यों पानी में आज भी पीलिया बहता और क्यों हल्के से तूफान से बिजली गुल होती। क्यों अस्पताल में आकर व्हील चेयर नहीं मिलती और क्यों दफ्तर की सीट पर सरकारी पगार पाने वाले की तस्वीर नहीं मिलती। प्रश्न सामान्य हैं, लेकिन उत्तरों की परिधि लंबी है। लंबे दौर की बहस में आम जनता के प्रश्न बौने हैं, क्योंकि सियासी करवटों ने सदन की बहस का कुआं खाली कर रखा है। सदन की मुंडेर पर न तो कौआ कांय कांय करता और न ही आगंतुक प्रश्नों को पूरा समय मिलता। इस बार सदन की दोपहर से पहले कई राजनीतिक ग्रहण प्रदेश में घूम रहे हैं। वातावरण आग बबूला है और जहां कई ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो हिमाचल की आशाएं-अभिलाषाएं अपनी जुबान, अपनी भाषा में सदन की कार्यवाही देखना चाहती हैं। विडंबना यह है कि राजनीति ने जो भाषा चुनी है, उसके अर्थ इस बार मानसून सत्र को क्रोधित, अंतहीत और मर्यादाविहीन कर सकते हैं। विडंबना भी यही है कि सदन की कार्यवाही अब दिनचर्या का अनुशासन नहीं और न ही बिजनेस का अनुशीलन है, बल्कि समय गुजारती अतिहीन राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही। बेशक ऐसे ही प्रश्न इस वक्त हिमाचल में सियासत की खेती कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों की जुबान फिसल रही है और ऐसा लगता है कि यहां की जनता-यहां के मतदाता किस खेत की मूली हैं। घायल प्रश्नों की खेप से आहत सत्ता और विपक्ष का सियासी चरित्र अगर गुत्थम-गुत्था है, तो हमारे सरोकार परेशान हैं-लज्जित हैं। कभी हिमाचल विधानसभा की कार्यवाहियों में हंसी-ठठोली का एक पक्ष सत्ता, दूसरा विपक्ष होता था। बड़े मद्दों की साझेदारी में विपक्ष की भागीदारी अगर बची ही नहीं, तो हंगामा सदन की पेशकश बनता रहेगा। बेशक बड़ी तैयारी में आएंगे इस बार दोनों पक्ष। प्रश्न अपनी व्यावहारिक अंगुलियां उठाएंगे तो जवाब के प्रदर्शन में सरकार की परिपक्वता, ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता से आएंगे वरना उत्तरों की धमाल में समाज के अर्थ बहरूपिए हो जाएंगे। बेशक विकास के सवालों पर हिमाचल विधानसभा का रिकार्ड अच्छा है, लेकिन आधुनिक संदर्भों में बहिर्गमन के पांव पूरा सदन चलने लगा है। हिमाचल के भविष्य के प्रश्न बढ़ती उधारी, घटते रोजगार, आपदाओं के दौर और प्रशासनिक सुधारों के वक्तव्य में अर्थ खोजते हैं। हिमाचल के लिए मानसून सत्र अगर बरसात की कुंडली खोले तो सरकार का प्रदर्शन और दिल्ली सरकार का रवैया सामने आएगा। प्रश्न यह नहीं कि गारंटियों में सरकार महिलाओं की तादाद को किस हद तक पंद्रह सौ रुपए दे पाई, बल्कि यह भी है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपदा राहत के पंद्रह हजार करोड़ रुपए कब आएंगे। कब पंजाब पुनर्गठन की भावना में हिमाचल को 7.19 प्रतिशत दर से अपने अधिकार मिल पाते हैं।

प्रश्न जनता की कचहरी से उठकर विधानसभा के कक्ष में उद्गार बनें, तो प्रदेश की असली सत्ता हितमतगार बनेगी। ये प्रश्न बाहें फैलाए हर बार विधानसभा के सत्रों से पूछते हैं कि फलां सडक़ पर गड्ढे क्यों हैं या ढह गई पुलिया पर दोबारा काम क्यों नहीं हुआ। अगर हम सडक़ दुर्घटनाओं में मारे गए सैकड़ों लोगों का वृत्तांत सुन लें, तो सत्र की चर्चा में सडक़, परिवहन, वाहन सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर विश£षण कर पाएंगे। अगर चिट्टे पर चर्चा करेंगे, तो शिक्षा की जरूरतों, अभिभावकों की मन्नतों और कानून-व्यवस्था के अमल पर संवेदनशील होंगे। क्यों पानी में आज भी पीलिया बहता और क्यों हल्के से तूफान से बिजली गुल होती। क्यों अस्पताल में आकर व्हील चेयर नहीं मिलती और क्यों दफ्तर की सीट पर सरकारी पगार पाने वाले की तस्वीर नहीं मिलती। प्रश्न सामान्य हैं, लेकिन उत्तरों की परिधि लंबी है। लंबे दौर की बहस में आम जनता के प्रश्न बौने हैं, क्योंकि सियासी करवटों ने सदन की बहस का कुआं खाली कर रखा है। सदन की मुंडेर पर न तो कौआ कांय कांय करता और न ही आगंतुक प्रश्नों को पूरा समय मिलता। इस बार सदन की दोपहर से पहले कई राजनीतिक ग्रहण प्रदेश में घूम रहे हैं।

दृष्टि कोण

इथेनॉल : भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आगे

नीट परीक्षा लीक के बाद आज मीडिया में सबसे बड़ा मुद्दा ई-20 यानी इथेनॉल ब्लैंडिंग पेट्रोल बना हुआ है। सरकार को इस बात पर घेरा जा रहा है कि वो लोगों पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोप रही है, जिससे उनकी माईलेज भी घट रही है और गाडियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं। भारत में इथेनॉल ब्लैंडिंग का सफर 2001 में शुरू हुआ। इससे पहले, गहन चर्चा हो रही थी कि भारत अपने जैव संसाधनों का इस्तेमाल करके भले ही पूरी तरह से नहीं, तो कम से कम आंशिक रूप से, ऊर्जा सुरक्षा कैसे हासिल कर सकता है। इसमें सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, बल्कि बंजर भूमि पर उगाए जाने वाले जेट्रोफा, पोंगामिया (करंज) जैसी फसलों से बनने वाले दूसरे बायो-ईंधन भी शामिल थे, जिनका इस्तेमाल विकल्प के तौर पर किया जा सकता था। हालांकि, इन बायो-ईंधन का कुछ हद तक इस्तेमाल 2001 से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल ब्लैंडिंग की पहली आधिकारिक घोषणा तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक द्वारा 2001 में स्वदेशी जागरण मंच के थिंक टैंक सीबीएमडी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी। यह कहा गया कि इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद कीमती विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2006 में पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई-5) का कार्यक्रम 20 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया। इसका अर्थ यह नहीं था कि इथेनॉल मिश्रण की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत पर स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। यह कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक कि इस ब्लैंडिंग में इथेनॉल का अनुपात बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ी। शुरुआती दौर में 5 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा गया। 2018 में 10 प्रतिशत ब्लैंडिंग का लक्ष्य 2022 तक हासिल करने का निर्धारण किया गया, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जून 2022 में निर्धारित समय से

पांच महीने पहले ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद यह ब्लैंडिंग बढ़कर 2022-23 में 12.06 प्रतिशत और 2023-24 में 14.60 प्रतिशत हो गई। 2024-25 में यह लगभग 19 प्रतिशत तक पहुंच गई। अंततः 2025-26 में भारत ने 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया, मूल 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले। शायद इथेनॉल ब्लैंडिंग का अनुपात जल्दी से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और अमरीका-ईरान युद्ध तथा उसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण सप्लाई में रुकावट थी। कार्बन उत्सर्जन : 2001 में जब पहली बार इथेनॉल ब्लैंडिंग के बारे में सोचा गया था, तो मुख्य जोर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता पर था, कार्बन उत्सर्जन कम करने पर उतना जोर नहीं था। लेकिन, नीति निर्माताओं के मन में यह बात जरूर थी कि इथेनॉल ब्लैंडिंग से पेट्रोलियम उत्पादों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन, जैसे-जैसे समय बीतता गया, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंता बढ़ती गई। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बढ़ता तापमान निश्चित रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाने और दूसरी औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा है। हाल के समय में, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए कई कोशिशें हुई हैं। जानकारों का मानना है कि इथेनॉल ब्लैंडिंग के कारण भी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होगा और इसे कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। हाल ही में, सरकार के पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर बेचने के फैसले पर काफी विवाद हुआ है। सबसे पहले, सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए मिलावटी पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है जिससे वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और आम जनता के वाहन खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। एक और आपत्ति यह है कि चूंकि इथेनॉल एक सस्ता घटक है और इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बनाने की लागत कम आती है, फिर भी सरकार कंपनियों से यह नहीं कह रही है कि वे इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। इथेनॉल मिलाने के खिलाफ तीसरी आपत्ति यह है कि इससे गाडियों का माइलेज कम हो जाता है, हालांकि अधिकारी मानते हैं कि माइलेज 2 से 6 प्रतिशत तक कम हो सकता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि माइलेज में कम से कम 10 से 15 प्रतिशत की कमी आती है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव : अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि कई देश पहले से ही इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राजस्थान पुलिस में यंग प्रोफेशनल्स भर्ती : आवेदन की बुधवार अंतिम तिथि

जयपुर (हिंस)। राजस्थान पुलिस में विशेषज्ञ युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर डेटा आधारित, तकनीक-सक्षम और आधुनिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए शुरू की गई *यंग प्रोफेशनल्स भर्ती* में आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 है। भर्ती पूरी तरह संविदा आधार पर होगी। एडीजी क्राइम बिपिन कुमार पांडे ने बताया कि कुल 5 पदों पर विशेषज्ञ युवाओं का चयन किया जाएगा। इनमें क्राइम डेटा एनालिस्ट, नवीन न्याय संहिताओं की मॉनिटरिंग, रोड सेफ्टी, ड्रग कंट्रोल और एआई इन पुलिसिंग के क्षेत्र शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म व विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन कमरा नंबर 217, द्वितीय तल, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर-302015 में जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।

प्रशासन के आश्वासन पर अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन फिलहाल स्थगित

अमृतसर (हिंस)। अमृतसर में किसान संगठनों की ओर से आज 11 अगस्त को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पलविंदर सिंह माहल ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने, वर्ष 2024 में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आज दोपहर 12 बजे रेलों का चक्का जाम करने का ऐलान किया था। माहल ने बताया कि इस संबंध में डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही थीं। किसानों की प्रमुख मांग थी कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि जारी की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ को एक साल बीतने के बावजूद कई प्रभावित परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एसएसपी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान प्रशासन ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया

कि बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे की राशि जारी करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2024 में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए संबंधित अधिकारी किसानों से संपर्क कर उनके बैंक खातों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। माहल ने कहा कि इन दोनों प्रमुख मांगों पर सरकार की सहमति बनने के बाद किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब स्तर की अन्य मांगों को लेकर कृषि मंत्री के साथ चंडीगढ़ में बैठक की जाएगी। माहल के अनुसार प्रस्तावित आंदोलन में पंजाब के 13 से 14 जिलों से किसान अमृतसर पहुंचने वाले थे। सरकार की ओर से दो प्रमुख मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद प्रदेश और जिला स्तर के किसान नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें आंदोलन स्थगित करने पर सहमति बनी। एसएसपी अमृतसर कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि किसान नेताओं के साथ डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और सिविल प्रशासन के अधिकारियों की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसानों की मांगों को संबंधित विभागों और मंत्रालयों तक लिखित रूप में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के बाद दोबारा बैठक कर किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। एसएसपी के अनुसार मुआवजे की बड़ी संख्या में अदायगी पहले ही की जा चुकी है। जिन किसानों का मुआवजा अभी बाकी है, उनकी सूचियां तैयार कर ली गई हैं और उन्हें भी जल्द मुआवजा दिया जाएगा।

कांग्रेस ने अशोक गहलोत को दरकिनार किया : पटेल

जोधपुर (हिंस)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम को खुश करने में लगे रहने के बयान पर पटेल ने कहा कि वे जोधपुर के हैं और सीनियर भी हैं। कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। मंत्री ने ओबीसी आयोग पर गोविंद डोटासरा के दिए बयान को भी गलत बताया। यह बात उन्होंने आज लूणी पंचायत समिति में विधायक जनसुनवाई केंद्र की शुरुआत के दौरान मीडिया से बातचीत में कही।। इस दौरान जोगाराम पटेल ने कोई भी राजनीतिक कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि डोटासरा और गहलोत पर अपनी बात रखी। जोगाराम पटेल ने अपने एक बयान में भाजपा सरकार में गहलोत सरकार से अपराध कम होने का दावा किया था। इसके बाद अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे पर पर इस दावे पर कहा था कि वो मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। जोगाराम पटेल से इस बयान पर मीडिया ने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि वे (अशोक गहलोत) जोधपुर के हैं और सीनियर भी हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारी ताकत है। विपक्ष मजबूत होता है तो जनता का काम होता है। मुझे विश्वास है विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दे उठाएंगे और सरकार के विकास की कमी-खामी को उठाएंगे। सरकार को मजबूत करेंगे। हम सभी मिलकर जनता के विकास के मुद्दों को लेकर उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के ओबीसी आयोग पर दिए बयान कि सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इस पर पटेल ने कहा कि राजनीतिक दल में काम करने वाला अपनी बात कहें। उनकी बात कितनी सही है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा वह सही नहीं है। वे बोले कि आज का दिन बड़ा अच्छा है, इसलिए आज राजनीतिक कमेंट नहीं करूंगा। मंत्री ने जनसुनवाई केंद्र की शुरुआत पर कहा कि सभी के प्रयासों से ये जनसुनवाई केंद्र की शुरुआत हुई है। सभी अधकिारी और जनप्रतिनिधि यहां बैठेंगे और यहां उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करेंगे। आने वाले कुछ महीनों के बाद इसका परिदृश्य बदल जाएगा। कुछ समय बाद ये झंवर पंचायत समिति हो जाएगी। ये एक ऐसा आयोजन है जहां सभी एक साथ मिले हैं इसलिए सभी भाइयों को राम-राम। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में प्रभु करे सभी को मौका मिले, हालांकि ये जनता पर निर्भर करता है।

डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह को दुष्कर्म के मामले में दस साल की सजा बरकरार

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 26 साल पुराने दुष्कर्म मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की कठोर कैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने पीड़ित युवती को छह लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह पूरा मामला 25 नवंबर, 2000 की रात का है। करीब 20 वर्षीय युवती पंजाब में नर्सिंग की छात्रा थी। उसके माता-पिता बाबा धनवंत सिंह के अनुयायी थे। परिवार चाहता था कि बेटी अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए उसकी मां उसे काउंसलिंग के लिए होशियारपुर के गांव पल्लियां झिक्की स्थित नूर विश्व रूहानी चैरिटेबल ट्रस्ट के डेरे में छोड़ गई थी। इसी दौरान युवती ने बाबा धनवंत सिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। कुछ सिख नेताओं की सलाह पर युवती और उसका परिवार मई, 2001 में तत्कालीन श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के सामने पेश हुआ। परिवार के मुताबिक उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा धनवंत सिंह को दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराकर कार्रवाई नहीं की गई। महिला आईपीएस अधिकारी वी. नीरजा की जांच के बाद अगस्त, 2002 में बाबा धनवंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर की अदालत ने वर्ष 2005 में बाबा धनवंत सिंह को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। बाबा धनवंत सिंह ने इसी वर्ष हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। पीडिता की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई थी। मामले में एडवोकेट नवकिरण सिंह ने पीड़िता की ओर से पैरवी की। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की सजा बरकरार रखी। अदालत ने टिप्पणी की कि पीडिता को आरोपी के हाथों यौन शोषण का सदमा झेलना पड़ा और उसे लंबे समय तक न्याय की तलाश करनी पड़ी।

गोयनका संगम-2026 : फतेहपुर शेखावाटी में जुटेंगे देश-विदेश के 600 सदस्य

सीकर (हिंस)। महानगरों और दुनिया के अलग-अलग देशों में कारोबार की ऊंचाइयां छू रहे गोयनका परिवारों के लिए सितंबर में अपनी जड़ों की ओर लौटने का खास मौका होगा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में *गोयनका संगम-2026* का आयोजन होगा, जिसमें देश-विदेश से करीब 600 लोग परिवार सहित पांच दिन तक अपने पूर्वजों की धरती पर रहेंगे। इस दौरान कुलदेवी बीरा बरजी दादी के मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ मातृभूमि, पारिवारिक विरासत और मारवाड़ी संस्कृति से जुड़ने का सिलसिला चलेगा। श्री शक्ति गोयनका ट्रस्ट कोलकाता के तत्वावधान में यह आयोजन सात से 11 सितंबर तक होगा। पांच दिवसीय कार्यक्रम में पूर्वजों की आत्मा की शांति तथा नई पीढ़ी की खुशहाली और प्रगति के लिए प्रार्थना के साथ शेखावाटी की सांस्कृतिक परंपराओं को मौखिक कथाओं, सामुदायिक आयोजनों और मंदिर कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। आयोजन में योग साधना, परिचय मिलन, संगोष्ठी, प्रेरणात्मक सत्र और धार्मिक प्रवचन

भी होंगे। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं इमामी समूह के प्रमोटर निदेशक सुशील कुमार गोयनका ने बताया कि संगम में देश-विदेश के प्रमुख कारोबारी परिवारों के सदस्य शामिल होंगे। इनमें आरपीजी समूह के चेयरमैन हर्ष गोयनका, आरपी-संजीव गोयनका समूह के चेयरमैन संजीव गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस समूह के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक एवं संपादकीय निदेशक विवेक गोयनका, वेलस्पन वर्ल्ड के चेयरमैन बीके गोयनका, जी समूह के चेयरमैन सुभाष चन्द्रा, इमामी समूह के संयुक्त चेयरमैन आरएस गोयनका, जीडी गोयनका स्कूल के संस्थापक अंजनी कुमार गोयनका, गोल्डन गोयनका समूह के चेयरमैन गिरधारी लाल गोयनका और गोल्डी स्पाइसेज के निदेशक आकाश गोयनका सहित अन्य प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। गोयनका रिकग्निशन अवार्ड समिति के चेयरमैन अरुण कुमार गोयनका ने बताया कि 10 सितंबर को व्यापार, समाज सेवा, खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले गोयनका समुदाय के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र व्यक्ति स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं। विजेताओं का चयन तीन सदस्यीय ज्यूरी करेगी और नामों की घोषणा सितंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि नगरीय विकास, आवासन एवं स्थानीय निकाय राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा अध्यक्षता करेंगे। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इसी रात कोटा की कृष्णा विजयवर्गीय द्वारा जागरण एवं ओढ़नी उत्सव आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट ने वर्ष 2019 में देश की प्रगति में योगदान देने वाले गोयनका परिवारों के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए इन वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत की थी। गोयनका संगम की धार्मिक गतिविधियों के तहत वृंदावन की कथावाचक साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी छह से आठ सितंबर तक तीन दिन प्रवचन देंगी। प्रवचनों में स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन में गोयनका समुदाय की नई पीढ़ी को पूर्वजों के इतिहास, परंपराओं, खान-पान, पहनावे और सामाजिक संस्कारों से परिचित कराने पर विशेष जोर रहेगा। गोयनका समुदाय का भारतीय उद्योग जगत में करीब तीन शताब्दियों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

राहुल गांधी भागो मत, गृहमंत्री सदन में जवाब देंगे : बेढ़म

जयपुर (हिंस)। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर युवाओं और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो संसद में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, ऐसे में राहुल गांधी सदन से बाहर प्रेस कांफ्रेंस करने के बजाए संसद में चर्चा में शामिल हों। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस लगातार सदन की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में यह सवाल ट्रेड कर रहा है- *राहुल गांधी भागो मत, देश के गृहमंत्री सदन में जवाब देंगे*। बेढ़म ने राहुल गांधी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और झारखंड में युवाओं के आंदोलन को लेकर अलग-अलग रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी को युवाओं और छात्रों की इतनी चिंता है तो झारखंड में छात्रों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर भी सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि वहां मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे और बाद में जंतर-मंतर पर छात्रों पर गोली चलाए जाने का दावा किया, जबकि उनके अनुसार छात्रों पर गोली नहीं चलाई गई। बेढ़म ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है।

सत्ता-विपक्ष की संकीर्ण राजनीति से दूर रहें *जेन-जी* : मायावती

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने छात्रों व नौजवान अर्थात *जेन-जी* से अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच इस समय चल रहे षड्यंत्र से दूर रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता और विपक्ष के लोग अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए इसका फायदा उठाएंगे। मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में पत्रकारवार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से सत्ता व विपक्ष के लोग किसी ना किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलन्त मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अंदरुणी मिलीभगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है और यह सब देश की जनता को सीधे-सीधे तौर पर काफी कुछ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र व नौजवान यानि कि जेन-जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा दु:खी व चिन्तित भी हैं, जिनको दूर कराने के लिए बसपा भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है। क्योंकि इनका यह आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बसपा लगातार गम्भीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। मायावती ने कहा कि देश को ऐसा नहीं लगना चाहिये कि छात्र व जेन-जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाए आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर अभी कुछ दिन पहले छात्रों, नौजवानों, जेन-जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहां इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने

हाईजैक कर लिया जो किसी से छिपा नहीं है। उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। अब झारखण्ड में भी पिछले काफी दिनों से वहां छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं अब वहां पर भाजपा और उनके समर्थक दल, उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली और अब झारखंड में हो रहे आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में छात्रों को हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की चार बार रही सरकारों में हमने छात्रों व नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया है। हमने छात्रों की समस्याओं का समय से निदान किया है और नौजवानों को, पूर्व की रही सरकारों में जो सरकारी भर्तियों में लम्बे अरसे से रोक लगा दी गई थी जिससे सभी विभागों के कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे थे, उसे भी ध्यान में रखकर व उसे हटाकर हमने यहां प्रदेश में लाखों-लाखों लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए हैं। इतना ही नहीं हमने पुलिस विभाग में व अन्य और विभागों में भी नये सरकारी पद सृजित करके यहां लाखों लोगों को रोजगार दिए। इस समय नौजवान एवं छात्र भी अपनी पढ़ाई व ट्रेनिंग आदि पूरी करने के बाद यही सब चाहते हैं, जिसे इस समय पूरे देश में केंद्र व राज्यों की विभिन्न पार्टियों की चल रही सरकारें यह सब उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं जिसकी वजह से इनमें रोष व्याप्त है। मायावती ने आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में तो अब दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी ना के बराबर रह गया है। बसपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता व विपक्ष की अन्दरूनी मिलीभगत से लोगों को लाचार बनाने की साजिश चल रही है, जिससे बचने के लिए अभी से ही इन वर्गों को प्रदेश सहित पूरे देश में सतर्क व सावधान हो जाना चाहिए।

मॉरीशस में गूंजेगी जयपुर की सनातन संस्कृति : पांच सदस्यीय विद्वान दल रवाना

जयपुर (हिंस)। छोटी काशी जयपुर की विद्वत्ता और भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश अब मॉरीशस में भी गूंजेगा। मॉरीशस के विश्वनाथ जनता मंदिर सोसाइटी (वीजेएमएस), गुडलैंड्स की ओर से आयोजित श्रावण महोत्सव-2026 में शिव कथा-प्रवचन और रुद्र महायज्ञ के लिए ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉ. महेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जयपुर से पांच सदस्यीय विद्वानों का दल बुधवार को मॉरीशस रवाना होगा। गुडलैंड्स स्थित श्रीविश्वनाथ परिसर में आयोजित महोत्सव में डॉ. मिश्रा व्यासपीठ से शिव कथा पर प्रवचन करेंगे तथा उनके नेतृत्व में श्री रुद्र महायज्ञ संपन्न होगा। इस दौरान भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान, सनातन संस्कार, संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों पर भी उद्बोधन होंगे। आयोजन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होकर कथा श्रवण और यज्ञ में आहुतियां देने की संभावना है। विश्वनाथ जनता मंदिर सोसाइटी पिछले 11 वर्षों से श्रावण महोत्सव आयोजित कर रही है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों और स्थानीय लोगों को कथा, यज्ञ, अनुष्ठान व आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। डॉ. मिश्रा के नेतृत्व में जाने वाले दल में पं. कमलेश शास्त्री, पं. दीपक शास्त्री वृंदावन, आचार्य कमलेश अचलपुरा और पं. सौम्य शास्त्री शामिल हैं।

दल महोत्सव के अलावा मॉरीशस में अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों में भी भाग लेगा। आचार्य डॉ. महेंद्र मिश्रा को वर्ष 2016 में विश्वनाथ जनता मंदिर सोसाइटी, मॉरीशस ने सम्मानित किया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ, मॉरीशस सरकार की टास्क फोर्स, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राजस्थान संस्कृत अकादमी सहित विभिन्न संस्थाओं से सम्मान मिल चुका है। उनके प्रमुख सम्मानों में ज्योतिष मार्तंड पं. जगन्नाथ सम्राट ज्योतिष सम्मान, याज्ञिक सम्राट, विवेकानंद गौरव सम्मान, पं. शिवचरण शास्त्री ज्योतिष सम्मान, मां शारदा अवार्ड, श्रीश्री याज्ञिक महासम्मान और श्रीगुरुदेव सेवा सम्मान शामिल हैं।

अधिकारी-कर्मी आवेदन के निष्पादन में सहयोग नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करें : मुख्यमंत्री

पटना (हिंस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में *राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम* में शामिल हुए। आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 181 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबद्ध विभाग शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके, जो भी अधिकारी या कर्मी आवेदन के निष्पादन में सहयोग नहीं करते हैं, कार्य में शिथिलता बरतते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बैठक के दौरान जहानाबाद की प्रिया, मुजफ्फरपुर के विभूति कुमार सिंह, नवादा की कांति देवी, सहरसा के शंकर कुमार सहित राज्य भर से आये हुए आवदेकों ने सहयोग शिविर कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित हो रहा है। कुछ मामले में संतुष्टि नहीं होने के कारण राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में हमलोग आये हैं और समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसके लिये मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और जिन आवेदकों को अब भी अपने आवेदन

के निर्णय पर आपत्ति है, उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी शिकायतों का पुन: परीक्षण कर न्यायसंगत एवं त्वरित निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराए गए हैं वो अतिक्रमण मुक्त बना रहे, यह सुनिश्चित करें। वृद्धा पेंशन तथा राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र उसका लाभ दिलाएं। कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद नई सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। सभी पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार करें तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती नवगछिया तिनटंगा जहाज घाट रोड, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क

भागलपुर (हिंस)। जिले के गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाली नवगछिया-तिनटंगा जहाज घाट रोड (14 नंबर सड़क) इस समय अपनी बदहाली के चरम पर है। सुशासन और चकाचक सड़कों के दावों के बीच यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर होकर तालाब में तब्दील हो चुका है। कहलगांव और तिनटंगा के बीच हाल ही में शुरू हुए मालवाहक जहाजों के परिचालन के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है, लेकिन सड़क का बुनियादी ढांचा इस बोझ को उठाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। वर्तमान में तिनटंगा करारी, गोपालपुर पेट्रोल पंप के पास, लत्तीपाकर और चपरघाट मोड़ जैसे प्रमुख स्थानों पर सड़क का नामोनिशान मिट चुका है। पूरी सड़क पर दो से तीन फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाता। भारी मालवाहक ट्रकों से लेकर ई-रिक्शा (टोटो) और दोपहिया वाहन आए दिन इन गड्ढों में पलट रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राहगीर अपनी जान हथेली पर रखकर इस मार्ग से

गुजरने को मजबूर हैं। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी के रास्ते माल ढुलाई के लिए तिनटंगा घाट का महत्व बढ़ा है। क्षमता से अधिक भारी वाहनों के लगातार गुजरने और जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था न होने के कारण पिच पूरी तरह उखड़ चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पथ निर्माण विभाग ने लंबे समय से इस सड़क की सुध नहीं ली है। केवल कागजी मरम्मत या मामूली ईंट-रोड़े गिराकर खानापूर्ति की जाती है, जो पहली बारिश में ही बह जाती है। इस क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के बाद सड़कों का कटाव होना आम बात है, जिसके बाद समय पर पुनर्निर्माण कार्य नहीं कराया गया। सड़क की इस दुर्दशा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने वाले नेता अब इस रास्ते पर आने से भी कतराते हैं। विधानसभा स्तर से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन ढाक के तीन पात वाली स्थिति बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय प्रक्रिया और टेंडर का बहाना बनाकर लगातार मामले को टाला जा रहा है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। सड़क की बदहाली से नाराज स्थानीय ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मुकेश कुमार और उदय (स्थानीय निवासी) ने बताया कि सड़क इतनी खराब है कि आए दिन टोटो पलट रहे हैं और स्कूली बच्चे व महिलाएं घायल हो रही हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाना किसी जंग जीतने जैसा है। नवीन कुमार (व्यवसायी) का कहना है कि व्यापार पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। जर्जर सड़क के कारण कोई भी मालवाहक गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती और वाहनों के मेंटेनेंस का खर्च दोगुना हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि पथ निर्माण विभाग और जिला प्रशासन ने जल्द ही इस जर्जर 14 नंबर सड़क का पक्का निर्माण शुरू नहीं कराया, तो वे लोग मुख्य मार्ग को जाम कर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

पीयू फोम बनाने वाली कंपनी शाम फोम का आईपीओ लान्च, 18 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

पालीयूरेथेन फोम (पीयू फोम) का उत्पादन और विपणन करने वाली कंपनी शाम फोम का 40.48 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 13 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 14 अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 17 अगस्त को अलाटेड शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त को बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लान्चिंग के बाद दोपहर दो बजे तक इस आईपीओ को सिर्फ सोलह आवेदन मिले थे, जिनके जरिये ये इश्यू महज 0.01 प्रतिशत सब्सक्राइब हो सका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 130 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है, जबकि लाट साइज 1,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 2,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,60,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 31.14 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इसमें कोई आफर फार सेल (ओएफएस) नहीं है।

इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 47.50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है। इसी तरह नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए भी 47.50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए पांच प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए कारपोरेट मेकर्स कैपिटल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। जेएंडके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

शाम फोम की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 2.97 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 3.58 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 8.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 73.89 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 81.62 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिकी अदालत ने गौतम अडाणी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

नई दिल्ली/न्यूयार्क। अमेरिका की एक अदालत ने अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी के खिलाफ प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामले स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कथित धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में 2 साल से जारी कानूनी कार्यवाही अब समाप्त हो गई है। न्यूयार्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फार द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ने न्याय विभाग के नियम 48(ए) के तहत दायर याचिका स्वीकार करते हुए आरोप पत्र में शामिल दूसरे, तीसरे और चौथे आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश निकोलस गैराफिस ने अभियोजन पक्ष से मामले को वापस लेने के फैसले पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने के बाद न्याय विभाग की याचिका को मंजूरी दे दी है। आरोपों को स्थायी रूप से खारिज किए जाने का अर्थ है कि आपराधिक कार्यवाही हमेशा के लिए समाप्त हो गई है और इन आरोपों को दोबारा दायर नहीं किया जा सकता। इन आरोपों में प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, वायर धोखाधड़ी की साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोप शामिल थे। गौतम अडाणी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने इसे विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ इसे स्वीकार किया है। अडाणी ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, इस चुनौतीपूर्ण दौर में सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में हमारा विश्वास कभी नहीं डिगा।

पावर ग्रिड में दिलचस्प बदलावः बीमा कंपनियों ने बढ़ाई हिस्सेदारी, एआईआई ने घटाई

नई दिल्ली। पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया (पीजीसीआईएल) में बड़े संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। जून 2026 तिमाही के आंकड़ों के अनुसार जहां घरेलू बीमा कंपनियों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाई है, वही विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी होल्डिंग में मामूली कमी की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश के बिजली पारेषण नेटवर्क की यह प्रमुख कंपनी अगले कुछ सालों के लिए एक विशाल आर्डर बुक के साथ मजबूत स्थिति में है, जिसका कुल मूल्य 1.76 लाख करोड़ रुपये है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 तक प्रमोटर (सरकार) की हिस्सेदारी 51.3 फीसदी पर स्थिर रही। हालांकि, संस्थागत निवेशकों के बीच हिस्सेदारी का पैटर्न बदल गया। बीमा कंपनियों ने इस अवधि में अपनी हिस्सेदारी 4.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.9 फीसदी कर ली, जो केवल छह महीनों में 2.4 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके विपरीत, विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी दिसंबर 2025 के 24.8 फीसदी से घटकर जून 2026 तक 24.3 फीसदी रह गई। म्युचुअल फंड और अन्य घरेलू संस्थानों की हिस्सेदारी भी थोड़ी घटकर 13.6 फीसदी पर आ गई। रिपोर्ट में हालांकि इन बदलावों के पीछे कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, और इससे सीधे तौर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बीमा कंपनियों का भरोसा बढ़ा है या विदेशी निवेशक दूर हो रहे हैं। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी भविष्य की विकास क्षमता और मौजूदा मजबूत आर्डर बुक है।

मारुति ग्रैंड विटारा की घरेलू बाजार में कुल 4,01,007 यूनिट्स की बिक्री दर्ज

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की लोकप्रिय एसयूवी ग्रैंड विटारा ने अपनी बिक्री के 4 लाख यूनिट्स के आंकड़े को छू लिया है। अपने लान्च होने के बाद से लेकर जून 2026 तक इस एसयूवी ने घरेलू बाजार में कुल 4,01,007 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जबकि 62,500 यूनिट्स का निर्यात भी किया गया है। यह उपलब्धि ग्रैंड विटारा ने 45 महीनों में हासिल की है, जिसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा शोरूम के माध्यम से बेचा जाता है। ग्राहक औसतन हर महीने 8,911 यूनिट्स और हर दिन लगभग 293 लोग इस एसयूवी को खरीद रहे हैं। हालांकि, 4 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में इसे दूसरी पीढ़ी की हुंडई क्रेटा के मुकाबले 21 महीने ज्यादा लगे, जिसने यह मुकाम 25 महीनों में हासिल कर लिया था। फिर भी, ग्रैंड विटारा ने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में कई रिकार्ड बनाए हैं; यह 1 लाख यूनिट (12 महीने में), 2 लाख यूनिट (22 महीने में, पहली पीढ़ी की क्रेटा को पीछे छोड़ते हुए) और 3 लाख यूनिट (कुल 10 महीने में 2 से 3 लाख तक) तक पहुंचने वाली सबसे तेज एसयूवी रही है।

सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च हुआ फैसिनेट टेक्सटाइल्स का आईपीओ, 13 अगस्त तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी फैसिनेट टेक्सटाइल्स का 66.98 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 13 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 14 अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 17 अगस्त को अलाटेड शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त को एनएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लान्चिंग के बाद दोपहर 2:30 बजे तक इस आईपीओ को सिर्फ 64 आवेदन मिले थे, जिनके जरिये ये इश्यू महज तीन प्रतिशत सब्सक्राइब हो सका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 148 रुपये प्रति शेयर से लेकर 156 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 800 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 1,600 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,49,600 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 42,93,600 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें लगभग 54 करोड़ रुपये के 34,57,600 नए शेयर जारी किये जा रहे हैं, जबकि करीब 13 करोड़ रुपये के 8,36,000 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए सिर्फ 1.01 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है।

इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 56.34 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 37.64 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.01 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए एफिलिटी ग्लोबल कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि मां कैमियो कारपोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं गिरिराज स्टाक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

फैसिनेट टेक्सटाइल्स की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 48 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 5.81 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 15.07 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 28.90 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 60.28 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 117.23 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 12.33 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 18.21 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ उछल कर 26.02 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 4.45 करोड़ रुपये के स्तर पर था। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ कर 10.45 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में ये 31.44 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर भी बढ़त हासिल करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 3.05 करोड़ रुपये के स्तर पर था। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस लगभग तीन गुने उछाल के साथ 9.04 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 21.14 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अनिंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 1.68 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 10.01 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए उछल कर 24.15 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

बैंकिंग सेक्टर के भविष्य पर दो दिवसीय मंथन, वित्त मंत्री करेंगी अध्यक्षता

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय अगले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के लिए दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 17 और 18 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और जमा बढ़ाने से लेकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने जैसे सात प्रमुख बिंदुओं पर एक प्रभावी रणनीति तैयार करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), नाबार्ड, सिडबी, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) सहित विभिन्न प्रमुख वित्तीय संस्थानों के लगभग 125 शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन भाग लेने वाले संस्थानों को बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने, बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले कदमों की पहचान करने और बैंक क्षेत्र के लिए समयबद्ध तथा व्यावहारिक रणनीति तैयार करने का मंच उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन में जिन सात प्रमुख विषयों पर मंथन होगा, उनमें जमा राशि जुटाना (ताकि सस्ते ऋण मिल सकें), युवाओं के लिए बैंकिंग सेवाएं, निवेश चक्र को समर्थन (खासकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए), वैश्विक क्षमता केंद्रों को सहयोग, कृषि और बागवानी मूल्य श्रृंखला के लिए बुनियादी ढांचा, क्रेडिट कार्ड कारोबार को नए सिरे से विकसित करना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना शामिल हैं।

देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चेन्नई में सोने की बढ़ी कीमत, चांदी में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में चेन्नई को छोड़कर देश के ज्यादातर दूसरे सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं चेन्नई में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की है। सर्राफा बाजार की दूसरी प्रमुख चमकीली धातु चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 430 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत 500 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 540 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है। कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,51,960 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,39,290 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,52,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,51,960 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है।

इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,51,960 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,52,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान कमजोरी के साथ बंद हुए। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निवेशक सतर्क होकर कारोबार करते रहे, जिसकी वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांकों पर दबाव बन गया। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 7,753.11 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.32 प्रतिशत टूट कर 26,605.36 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के साथ 53,964.19 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,862.50 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,726.03 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक तेजी के साथ 26,323.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक कमजोरी के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। वहीं जापान के टोक्यो स्टाक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से निक्केई इंडेक्स में कोई हलचल नहीं है।

कोस्पी इंडेक्स 83.02 अंक यानी 1.32 प्रतिशत उछल कर 6,382.68 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 50.53 अंक यानी 0.89 प्रतिशत की मजबूती के साथ 5,748.96 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताईवान वेटेड इंडेक्स 200.85 अंक यानी 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 45,129.61 अंक के स्तर पर आ गया है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 95.50 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,536 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,618.40 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.76 प्रतिशत लुढ़क कर 6,317.06 अंक के स्तर पर, हैंग सेंग इंडेक्स 158.49 अंक यानी 0.61 प्रतिशत टूट कर 25,779 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 3,964.79 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का आईपीओ, 17 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

डेयरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने का काम करने वाली कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड का 1,553 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 13 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 14 अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 17 अगस्त को अलाटेड शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। लान्चिंग के बाद दोपहर 1:15 बजे तक इस आईपीओ को 40 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल चुका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 133 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 107 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लाट यानी 107 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,980 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,94,740 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 1,391 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड के इस आईपीओ के तहत दो रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 11,09,43,193 शेयर जारी होंगे। इनमें लगभग 1,428 करोड़ रुपये के 10,20,14,623 नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 125 करोड़ रुपये के 89,28,570 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जाएंगे। आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है। केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो प्रास्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 19.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 46.07 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 127.01 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 1,826.86 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 2,354.79 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 3,145.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में कंपनी के कर्ज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 1,036.72 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 1,376.38 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 1,671.85 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 197.05 करोड़ रुपये के स्तर पर था। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ कर 242.77 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में ये 378 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इस अवधि में कंपनी को इस मोर्चे पर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 278.04 करोड़ रुपये के स्तर पर था। हालांकि इसके अगले साल 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस घट कर 199.23 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

चोट के कारण हैम्पशायर के अगले मैच से बाहर हुए आशुतोष शर्मा

लंदन

भारतीय आलराउंडर आशुतोष शर्मा चोट के कारण हैम्पशायर के लिए डर्बीशायर के खिलाफ होने वाले वनडे कप मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। आशुतोष को मुकाबले के दौरान चोट लगी थी। हालांकि, हैम्पशायर ने उनकी चोट की प्रकृति और गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

हैम्पशायर ने जानकारी में आशुतोष की अनुपलब्धता की पुष्टि की। टीम ने कहा, आशुतोष शर्मा मैच के दौरान लगी चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं। प्रतियोगिता के शुरुआती तीन मैचों में खेलने वाले तेज गेंदबाज हैरी पेट्री की टीम में वापसी हुई है।

वनडे कप में आशुतोष का बल्ले से प्रदर्शन इस सत्र में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। उन्होंने सात मैचों में सिर्फ 56 रन बनाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 16 रन रहा है। हालांकि, गेंद से उन्होंने शानदार प्रभाव छोड़ा है और वह हैम्पशायर के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आशुतोष ने सात मैचों में 14 विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 15.92 रहा है।

बल्लेबाजी में संघर्ष के बावजूद गेंद से उनके प्रदर्शन को टीम के लिए बड़ा सकारात्मक पक्ष माना जा रहा है।

आशुतोष की चोट ऐसे समय आई है जब हैम्पशायर के लिए प्रतियोगिता का अगला चरण हासिल करना महत्वपूर्ण है। टीम सात मुकाबलों में चार जीत के साथ अपने ग्रुप में चौथे स्थान पर है और अगले दौर में जगह बनाने के लिए उसे आगे के मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

आशुतोष की जगह हैरी पेट्री को टीम में शामिल किया गया है। पेट्री ने प्रतियोगिता के शुरुआती तीन मैचों में हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व किया था।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आशुतोष की चोट कितनी गंभीर है और क्या वह मुकाबले के बाद होने वाले अन्य मैचों के लिए भी उपलब्ध रह पाएंगे। आशुतोष दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में खेलते हैं। पिछले दो आईपीएल सत्रों में उन्होंने दिल्ली के लिए 350 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 170 और बल्लेबाजी औसत 31.25 रहा है।

आशुतोष ने 2017 में मध्य प्रदेश के साथ अपना घरेलू क्रिकेट करियर शुरू किया था और बाद में रेलवे से जुड़े।

उन्होंने अब तक सभी प्रारूपों में 92 मैच खेले हैं। 50 ओवर के प्रारूप में 21 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 458 रन और दो विकेट हैं।

आईपीएल में उन्हें पहली पहचान पंजाब किंग्स के साथ मिली, जहां उन्होंने इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के रूप में पदार्पण करते हुए 17 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेली थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 2025 सत्र से पहले उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा था।

न्यूज ब्रीफ

आर्यन गौर ने दूसरे छोर पर निभाई अहम भूमिका : अनुज रावत

नई दिल्ली। कप्तान अनुज रावत की 92 रन की तूफानी पारी और आर्यन गौर के नाबाद अर्धशतक की बदौलत

पुरानी दिल्ली 6 ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में आउटर दिल्ली वारियर्स को सात विकेट से हराया। जीत के बाद रावत ने अपनी पारी और आर्यन गौर के साथ साझेदारी को टीम की सफलता में अहम बताया। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 ने नौ रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रावत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला, जबकि गौर ने दूसरे छोर पर उनका शानदार साथ दिया। रावत ने कहा, विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए योजना सामान्य तरीके से खेलने और कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं करने की थी। हालांकि, जब बाएं हाथ के स्पिनर ने गेंदबाजी शुरू की और हमने शुरुआती दो विकेट गंवा दिए, तो मुझे लगा कि टीम के लिए आगे आकर प्रभावशाली पारी खेलना जरूरी है। गौर के साथ साझेदारी पर उन्होंने कहा, जब मैंने एक अच्छा शाट लगाया तो लय बननी शुरू हो गई और आर्यन ने भी दूसरे छोर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावत ने महज 38 गेंदों में 92 रन बनाए, जबकि आर्यन गौर ने 40 गेंदों में नाबाद 57 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर पुरानी दिल्ली 6 को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और टीम ने 16वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

सरफराज की जगह जय गोहिल दलीप ट्राफी के लिए वेस्ट जोन टीम में शामिल

मुम्बई। बल्लेबाज सरफराज खान को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किये जाने से 25 साल के युवा बल्लेबाज जय गोहिल की भी किस्मत खुल गयी है। इस कारण जय को दिलीप ट्राफी के लिए वेस्ट जोन टीम में जगह मिल गयी है। सरफराज को चोटिल साई सुदर्शन के स्थान पर टीम में जगह मिली है। इससे घरेल क्रिकेट में दलीप ट्राफी में वेस्ट जोन की टीम में उनकी जगह खाली हो गई थी। जो अब जय को मिल गयी है। गौरतलब है कि सौराष्ट्र के बल्लेबाज जय गोहिल के पहले वेस्ट जोन टीम में स्टैंडबाय खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गय था। वही अब उन्हें अब मुख्य दल मे शामिल कर लिया गया है। इससे गोहिल के पास अपनी प्रतिभा को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर है। गौरतलब है कि गोहिल ने हाल ही में साल 2022-23 रणजी ट्राफी सत्र में सौराष्ट्र की ओर से छह मैचों में 58.11 के बेहतरीन औसत से कुल 523 रन बनाए थे, जिसमें एक शानदार शतक और चार अर्धशतक शामिल थे। उनके इस प्रदर्शन से चयनकर्ताओं ने दलीप ट्राफी में उन्हें जगह दी है। अपने फर्स्ट-क्लास करियर में भी गोहिल ने लगातार रन बनाए हैं। अब तक खेले गए कुल 12 मैचों में, उन्होंने 47.77 के औसत से 860 रन बनाये हैं, इससे उनकी उनकी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता सामने आयी है।

टी20 विकेटकीपरों में डी काक के नाम है सबसे ज्यादा शिकार

मुम्बई। विश्व क्रिकेट में एक से बढ़कर एक विकेटकीपर हुए हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी काक, से

लेकर भारत के महेन्द्र सिंह धोनी और इंग्लैंड के जोस बटलर हैं। वहीं अगर टी20 प्रारुप की बात करें तो डी काक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की सूची में नंबर एक पर हैं। वही इंग्लैंड के बटलर दूसरे और धोनी तीसरे स्थान पर हैं। डी काक ने अपने टी-20 अंतर्राष्ट्रीय करियर (2012-2026) में 110 मैचों की 109 पारियों में विकेटकीपिंग करते हुए कुल 117 शिकार किए हैं, जो इस प्रारूप में किसी भी विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक है। इनमें 98 कैच और 19 स्टंपिंग शामिल हैं। उनकी प्रति पारी 1.073 शिकार की औसत और एक पारी में अधिकतम चार कैच लपकने की क्षमता उनकी फुर्ती का प्रमाण है, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम को कई बार जीत मिली। वहीं इंग्लैंड के बटलर दूसरे स्थान पर हैं। साल 2011 से 2026 तक के अपने लंबे टी-20 करियर में, बटलर ने 130 पारियों में विकेटकीपर के रूप में 109 शिकार किए हैं, जिनमें 87 कैच और 22 स्टंपिंग शामिल हैं। उनका प्रति पारी शिकार औसत 0.838 रहा है, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है। एक पारी में अधिकतम पांच शिकार (चार कैच और एक स्टंपिंग) उनके नाम है। वहीं भारत के धोनी ने साल 2006 से 2019 के बीच 97 पारियों में 91 शिकार किए और इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, उनका सबसे बड़ा प्रभाव 34 स्टंपिंग के विश्व रिकार्ड में दिखता है, जो इस प्रारूप में किसी भी विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक है। 57 कैच के साथ, तेजी से स्टंपिंग करने में उनका कोई जवाब नहीं था। उनका प्रति पारी शिकार औसत 0.938 रहा और उन्होंने एक पारी में अधिकतम पांच कैच भी लपके थे।

हाकी विश्व कप में भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार

15 अगस्त को पहले मुकाबले में वेल्स से होगा सामना

नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हाकी टीम 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच हाकी पुरुष विश्व कप 2026 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार है। भारत को विश्व कप में पूल डी में रखा गया है और उसका पहला मुकाबला 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ होगा। इसके बाद 17 अगस्त को उसे इंग्लैंड और 19 अगस्त को परंपरागत-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना है। भारतीय टीम इस बार 51 साल बाद हाकी विश्व कप का खिताब अपने जीतने के प्रयास करेगी। इससे पहले उसने साल 1975 में ये खिताब अजीत सिंह की कप्तानी में जीता था। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारतीय हाकी फेडरेशन ने कई युवा और उभरते हुए खिलाड़ियों को शामिल किया है।

टीम में शामिल गोलकीपर मोहित एचएस, डिफेंडर यशदीप सिवाच और मिडफील्डर राजिंदर सिंह व आदित्य अर्जुन लालगे जैसे खिलाड़ियों से टीम को बड़ी उम्मीदें हैं। इन्होंने अपने हाल के प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है और अब विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। टीम में शामिल होने वाले 23 वर्षीय मिडफील्डर आदित्य अर्जुन लालगे विश्वकप में लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका ध्यान देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है। आदित्य ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों और कोचों के निरंतर मार्गदर्शन से उनका मनोबल बढ़ता है। उनकी पूरी टीम एक ही लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं मध्यपंक्ति के साथी खिलाड़ी राजिंदर सिंह ने टीम की एकजुटता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उनके अनुसार, खिलाड़ी मैदान के अंदर और बाहर एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं और किसी भी गलती पर तत्काल सहायता के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर डिफेंडर यशदीप सिवाच ने बताया कि विश्व कप की तैयारियां बेहद गहन और कड़ी रही हैं। फिटनेस, तकनीकी कौशल और रणनीतिक बारीकियों के हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया है। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से मिले मार्गदर्शन को अपने खेल के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना।

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में होगी ऋषभ की कड़ी परीक्षा, असफल रहे तो खतरे में पड़ जाएगा भविष्य

कोलंबो। खराब फार्म से गुजर रहे भारतीय टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज बेहद अहम है। टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इस सीरीज में अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करना होगा। सीरीज से पहले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में वह फिर रन बनाने में असफल रहे जिससे उनके प्रशंसकों के साथ ही टीम प्रबंधनर की भी चिन्ताएं बढ़ गयी हैं। पिछले कुछ समय से वह मैदान पर लापरवाही से खराब शाट लगाने के कारण आउट हो रहे हैं। इससे उनके खेल के प्रति रवैये पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही उनका भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। वह अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे। जिसका कारण उनके लापरवाही भरे शाट हैं। अभ्यास मैच में भी उन्होंने यही गलती दोहरायी। वह दोनों पारियों में विफल रहे। पहली पारी में वह मात्र 2 रन जबकि दूसरी पारी में केवल 28 रन बना पाये। इन दोनों ही पारियों में पंत का बल्लेबाजी करने का तरीका बेहद लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना लगा। उन्होंने ऐसे शाट खेलने की कोशिश की मानो वह किसी गली क्रिकेट मैच में खेल रहे हों। वह कभी बाहर जाती गेंद को पैर से मारकर तो कभी गैरजरी शाट खेलकर अपना विकेट खोते दिखे। उनका यह रवैया दर्शाता है कि वह अपनी बल्लेबाजी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए यह बेहद आवश्यक है। वैसे तो वह अपने अनूठे और जोखिम भरे शाट्स के लिए जाने जाते हैं पर लगातार मिल रही असफलताओं के बीच उन्हें अपने खेल पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है। यह लापरवाही केवल अभ्यास मैच तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे करियर पर भारी पड़ रही है, खासकर जब टीम इंडिया में उनकी जगह लेने के लिए ध्रुव जुरेल और ईशान किशन जैसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार बैठे हैं, जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। यदि वह इसी तरह खेलते रहे तो तो टीम से बाहर होना तय है।

लिवरपूल ने बार्सिलोना के डिफेंडर रोनाल्ड अराउहो के साथ लोन पर किया करार

लिवरपूल

इंग्लिश फुटबाल क्लब लिवरपूल ने बार्सिलोना के डिफेंडर रोनाल्ड अराउहो को 2026-27 सत्र के लिए लोन पर साइन करने पर सहमति बना ली है। क्लब ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह करार सफल वर्क परमिट आवेदन और अंतरराष्ट्रीय मंजूरी मिलने के अधीन है।

27 वर्षीय उरुग्वे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अराउहो बार्सिलोना के लिए 200 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं। वह 2018 में क्लब से जुड़े थे और तब से तीन बार स्पेनिश ला लीगा खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। इनमें पिछला सत्र भी शामिल है। इस साल की शुरुआत में उन्हें बार्सिलोना का कप्तान भी नियुक्त किया गया था।

लिवरपूल से जुड़ने के बाद अराउहो टीम में 33 नंबर की जर्सी पहनेंगे

क्लब की वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं शुरुआत करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत-बहुत खुश हूं। मैं इस बड़े क्लब का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं, जिसका शानदार इतिहास है। मैं अपने नए साथियों से मिलने और खेलना शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। मैं बेहद प्रेरित हूं और शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।

अराउहो ने कहा कि लिवरपूल से जुड़ना उनके करियर के इस पड़ाव पर सही फैसला है। उन्होंने कहा,

मुझे लगता है कि मेरे करियर के इस चरण में यह मेरे लिए आदर्श कदम था। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए जरूरी कदम था। जैसे ही मुझे लिवरपूल की रुचि के बारे में पता चला, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। मैं यहां आकर बेहद खुश हूं और शुरुआत करने के लिए उत्साहित हूं। यह सही समय पर सही कदम था।

सेंटर-बैक के रूप में खेलने वाले अराउहो जरूरत पड़ने पर राइट-बैक की भूमिका भी निभा सकते हैं। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उरुग्वे के रेंटिस्टास क्लब से की थी। इसके बाद एक सत्र बोस्टन रिवर के लिए खेलने के बाद वह यूरोप पहुंचे और बार्सिलोना से जुड़े। शुरुआत में उन्होंने क्लब की बी टीम के लिए खेला।

बार्सिलोना की सीनियर टीम में अराउहो ने 2019 में पदार्पण किया और 2020-21 सत्र से टीम में नियमित रूप से अपनी जगह बना ली। अब तक वह क्लब के लिए 213 मैचों में 14 गोल कर चुके हैं।

बार्सिलोना के साथ अराउहो ने दो कोपा डेल रे, तीन स्पेनिश सुपर कप और तीन ला लीगा खिताब जीते हैं। उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम के लिए वह 27 मैच खेल चुके हैं और एक गोल उनके नाम है।

यूरोपीय एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा

यूरोपीय एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में ब्रिटेन की एथलीट एमी हंट ने स्वर्ण पदक जीता।

कामनवेल्थ के तीन पदक विजेता केबीसी में आएंगे नजर

नई दिल्ली

कामनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए पदक जीतने वाले पैरा एथलीट शर्मिला धनकर, बाक्सर लवलीना बोरगोहेन और पैरा-पावरलिफ्टर झंडू कुमार जल्द ही लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में नजर आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को शो के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हाट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। आईएएनएस के मुताबिक, ग्लासगो कामनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं पर आधारित विशेष एपिसोड 15 अगस्त के बाद प्रसारित किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान तीनों खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के साथ-साथ संघर्ष और सफलता की कहानी भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे।

घरेलू हिंसा से कामनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण तक शर्मिला का सफर

पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने कामनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के एफ57 शाट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उनकी जिंदगी का संघर्ष और खेल के क्षेत्र में हासिल की गई सफलता उन्हें खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। घरेलू हिंसा से बचकर अपने जीवन को नई दिशा देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने तक शर्मिला का सफर

बेहद प्रेरणादायी रहा है। केबीसी के मंच पर उनकी कहानी दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र हो सकती है।

लवलीना ने बाक्सिंग में जीता रजत

भारतीय बाक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कामनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 75 किग्रा कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं लवलीना खेलों में अपनी निरंतर सफलता के लिए जानी जाती हैं। केबीसी के विशेष एपिसोड में वह अपने बाक्सिंग करियर, चुनौतियों और कामनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने के अनुभवों को साझा करती नजर आएंगी।

झंडू कुमार ने दिलाया भारत को पहला पदक

पैरा-पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट इवेंट में कांस्य पदक जीतकर कामनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक हासिल किया था। उन्होंने 190 किग्रा की अपनी सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए थे। झंडू की उपलब्धि ने पैरा-स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती ताकत को भी सामने रखा। केबीसी के मंच पर वह अपने खेल सफर और संघर्ष की कहानी अमिताभ बच्चन के साथ साझा करेंगे।

39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा भारत

ग्लासगो में आयोजित कामनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय दल ने कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल रहे। कुश्ती, शूटिंग और हाकी जैसे भारत के मजबूत खेलों के शामिल नहीं होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खास तौर पर एथलेटिक्स में प्रदर्शन ने देश के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई।

अल्काराज के बाद सिनर भी सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटे

रोम

स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बाद विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने भी फिट नहीं होने के कारण सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। पांच बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सिनर अभी तक अपनी घटने की चोट से नहीं उबर पाये हैं। इससे सिनर के प्रशंसकों को झटका लगा है। सिनर गत माह विंबलडन में मिली जीत के बाद से ही टीम से बाहर हैं। वहीं अल्कराज ने कलाई की चोट के कारण अपना नाम वापस ले लिया था। सिनसिनाटी ओपन में पुरुष एकल वर्ग के मुकाबले शनिवार से शुरु होने जा रहे हैं। जिनका आकर्षण इन दोनो के नहीं होने से कम होगा। सिनर ने कहा है कि दाहिने घुटने में दर्द के कारण अभी वह खेलने की हालत में नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अपने डाक्टरों से परामर्श करने के बाद, मैंने सिनसिनाटी में होने वाले मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट से

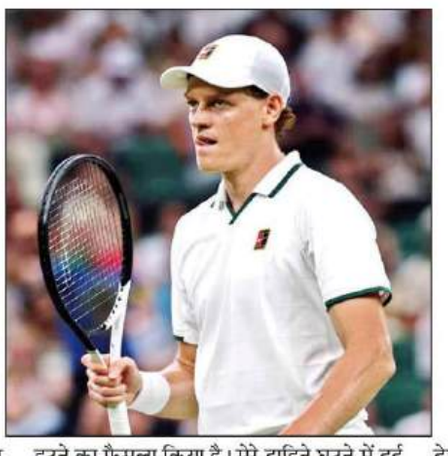

हटने का फैसला किया है। मेरे दाहिने घुटने में दर्द है और मैं अभी खेलने के लिए तैयार नहीं हूं।

गौरतलब है कि सिनर ने इससे पहले टोरंटो में होने वाले टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया था। इस प्रकार से बाहर रहने से आगामी अमेरिकी ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंटों में उनकी तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने अब तक के करियर में, सिनर ने पांच ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और अभी वह पुरुष टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरा हैं। वह लगातार बड़े टूर्नामेंटों में असाधारण प्रदर्शन करते आए हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। हालांकि, करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए उन्हें अभी फ्रेंच ओपन का खिताब जीतना बाकी है। आस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और अन्य ग्रैंड स्लैम में सफलता हासिल करने के बाद, फ्रेंच ओपन उनके करियर का अगला बड़ा लक्ष्य बना हुआ है, और प्रशंसक उन्हें इसमें जीतते हुए देखना चाहते हैं। सिनर से पहले अल्काराज ने भी कलाई की चोट के कारण इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था।

प्रशंसकों को उम्मीद, वैभव तोड़ सकते हैं लारा का 400 रनों का रिकार्ड

मुम्बई। 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिस प्रकार से अब तक खेला है। इससे उनके प्रशंसकों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का 400 रनों का विश्व रिकार्ड तोड़ सकते हैं। वैभव ने हालांकि अभी तक भारतीय टीम से केवल टी20 प्रारुप में ही खेला है पर जिस प्रकार की प्रतिभा उनमें पायी गयी है उससे तय है कि भविष्य में कई रिकार्ड तोड़ सकते हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए टेस्ट और एकदिवसीय प्रारुपफार्मेट में भी उनके डेब्यू की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब वैभव लाल गेंद से खेली जाने वाली प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता दिलीप ट्राफी में खेलते हुए दिखेंगे। वैभव का कहन है कि व भारतीय टीम के लिए टेस्ट प्रारुप में खेलना चाहते हैं और उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वैभव के लिए हालांकि स्ट क्रिकेट में अपनरे को स्थापित करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यह प्रारूप संयम और धैर्य की कसौटी होता है। वैभव अभी तक जिस भी सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में उतरे हैं, उन्होंने कोई न कोई रिकार्ड बनाया या तोड़ा है. ऐसे में अगर उन्हें टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिलता है, तो उनके निशाने पर लारा का वह ऐतिहासिक रिकार्ड होगा। इस रिकार्ड को तोड़ने के इस ऐतिहासिक उपलब्धि को तोड़ने के लिए भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी कई बार प्रयास किए, लेकिन वे कभी इसमें सफल नहीं हो पाए। वहीं क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि वैभव में वह असाधारण प्रतिभा है, जो लारा के टेस्ट क्रिकेट के इस सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के रिकार्ड को ध्वस्त कर सकती है।

नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानें?

जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वो जाने-अनजाने में आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। कहीं न कहीं हम उनकी तरह बात करने, उनकी तरह बनने और वैसा ही करने की कोशिश अनजाने में करने लगते हैं, ये मानवीय पकृति है जिसे हर कोई करता है और इसे बदलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि संगत का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग एक जटिल अंग है जिसे समझ पाना असंभव है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि जो लोग हमारे साथ या आसपास हैं वो कितने बेकार और नकारात्मक सोच वाले हैं। ऐसे लोग विषैले सांप की तरह होते हैं जो कभी न कभी आपको भी नुकसान पहुंचाते ही हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोग अपनी बातों या अपने कामों से आएं दिन किसी न किसी का दिल दुखाते रहते हैं। वे हमेशा कोशिश करेंगे कि वे आपको बहुत भला चाहते हैं लेकिन आपको निराश करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को स्मार्टली हैंडल करना सीखें और उनसे भावनात्मक दूरी बना लें। वरना वे आपमें भी ऐसी आदत पनपा सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। चाहें परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों न हों, उन्हें हमेशा शिकायत और समस्या ही रहती है। समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। जो लोग आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं बल्कि हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं वे लोग टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं। जितना संभव हो, ऐसे लोगों से दूर रहें। जहरीले स्वभाव वाले लोगों से आप जब भी बात करें, तो वे दूसरों के बारे में हमेशा खराब ही बोलेगें। इससे आपके नजरिए पर भी असर पड़ता है। इसलिए, अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें।

डीवीडी देखकर व्यायाम न करें...

एक नए शोध में पता चला है कि फिटनेस डीवीडी देखते हुए घर में व्यायाम करने का विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के परिणामों से पता चला है कि इस तरह के वीडियो से व्यक्ति की सोच नकारात्मक दिशा की ओर मुड़ सकती है और उनके प्रेरणा स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिटनेस के लिए मिलने वाली डीवीडी के अध्ययन से यह भी सामने आया है कि इस तरह की डीवीडी में इस्तेमाल होने वाली निराशाजनक भाषा से व्यायाम करने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव का स्तर कम हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा वीडियो देखने वाले व्यक्तित की आशा और क्षमता पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बन सकता है। इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने व्यायाम का प्रशिक्षण देने वाले 10 लोकप्रिय डीवीडी की समीक्षा की। इस तरह के डीवीडी में इस्तेमाल होने वाली भाषा और वीडियो का मूल्यांकन किया गया। इस शोध का लक्ष्य इस तरह के डीवीडी में दिए जाने वाले संदेशों और वीडियो को बेहतर तरीके से समझना और उपयोगतकर्ताओं पर इनके प्रभाव का आकलन करना था। इन फिटनेस डीवीडी का 25 करोड़ डॉलर का उद्योग है, लेकिन इनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इस शोध के परिणामों के बाद सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया कि वे इस तरह के डीवीडी को खरीदते समय या इनका इस्तेमाल करते समय इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूक रहें।

सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी मिल सकता है दाखिला

सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों के दाखिले की भी अनुमति दी जा सकती है। करीब 55 साल पहले जब एक सैनिक स्कूल खुला था तो वह सिर्फ पुरुष प्रधान ही था यानी सिर्फ छात्रों का ही दाखिला होता था। मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजापति राजू ने एक पत्र लिखा था जिसके आधार पर रक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला देने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय अभी देश भर में 22 सैनिक स्कूल चलाता है। अधिकारी ने बताया कि राजू ने रक्षा मंत्री मनोहर पारिज्कर को एक पत्र लिखकर आग्रह किया जिस पर पार्रिकर ने इस मामले पर गौर करने का वादा किया। देश भर में नैशनल डिफेंस अकेडमी और आर्मी में महिलाओं के दाखिले को लेकर विभिन्न स्तरों पर बहस चल रही थी। सैनिक स्कूल में छात्राओं के प्रवेश को इस दिशा में पहला कदम माना जाएगा।

रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में राजू ने उल्लेख किया, 'आज के आधुनिक समय में रक्षा सेवाएं अपवाद नहीं रह गई हैं जहां महिलाएं अपनी भूमिका न निभा सकें। इस संदर्भ में मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कई पैरंट्स सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा (विजयनगरम) के माध्यम से देश की सेवा में अपनी लड़कियों को भेजना चाहते हैं।'

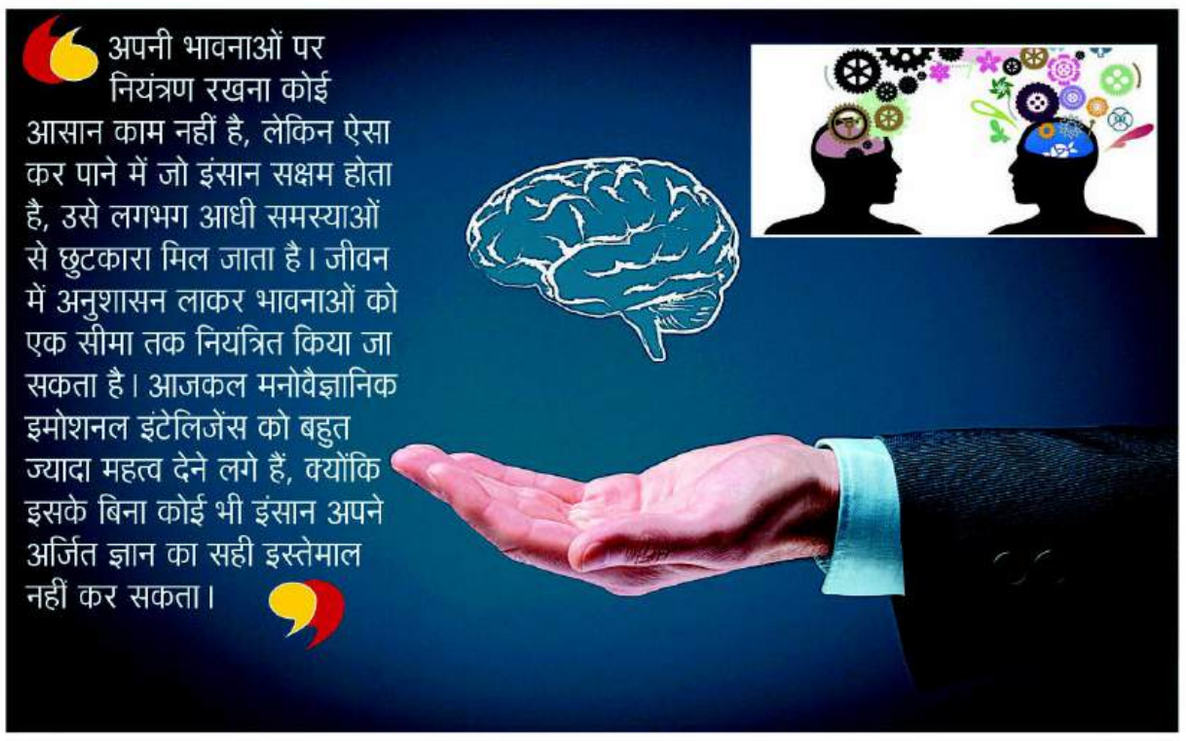

इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी...

आज की जटिल जीवन स्थितियों में खुशी और कामयाबी हासिल करने के लिए व्यक्ति का केवल मेहनती और बुद्धिमान होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता भी बहुत जरूरी है। आपने यह अनुभव किया होगा कि एक ही जैसी स्थितियों में लोग अलग-अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।कुछ लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हताश हो जाते हैं तो कुछ बेहद मुश्किल हालात में भी घबराने के बजाए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें से दूसरी तरह के लोग भावनात्मक रूप से बुद्धिमान माने जाते हैं और वे जीवन के हर मोर्चे पर कामयाब होते हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक भावनात्मक विवेक को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान अपने अर्जित ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। भावनात्मक विवेक के सिद्धांत के प्रतिपादकों का ऐसा मानना है कि पारंपरिक रूप से जिसे हम आइक्यू कहते हैं, उसका क्षेत्र बहुत सीमित है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का दायरा बहुत विस्तृत है।

क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस

इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत समस्त मानवीय व्यवहार समाहित हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत करके तकनीकी कौशल सीखना और जानकारियां हासिल करना ही काफी नहीं, बल्कि इंसान को अपनी भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी आना चाहिए। बौद्धिक रूप से कोई भी इंसान चाहे कितना ही सक्षम क्यों न हो लेकिन भावनात्मक परिपक्वता के अभाव में वह असफल हो सकता है।

अंतर्मन के आईने में

अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझना भी भावनात्मक विवेक का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप किन बातों से खुश होते हैं, कौन सी बातें आपको नापसंद हैं, अगर कभी आपका मूड खराब है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस वजह से आपका मूड खराब है। किन बातों को लेकर आप चिंतित और परेशान होते हैं, आपके मन में किन बातों को लेकर असुरक्षा है, यह आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। जब कभी आप शांतिपूर्वक अकेले बैठे हों तो तटस्थ हो कर दूसरों की नजर से आत्मविश्लेषण करें। जब आप ईमानदारी के साथ अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे, तभी आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होंगे। इससे अपने मनोभावों को नियंत्रित और संतुलित करना आपके लिए सहज होगा।

भावनात्मक अनुशासन

अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाने में जो इंसान सक्षम होता है, उसे लगभग आधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में अनुशासन लाकर भावनाओं को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढेंगे और जीवन के लिए यह दिशा-निर्देश तय करेंगे कि मन में नकारात्मक भावनाओं को आने नहीं देना है तो क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष जैसी भावनाओं से काफी हद तक ऊपर उठ सकते हैं। अगर कोई क्रोध में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में आपका नाराज होना उचित नहीं है। उस वक्त आप शांत रहें और बाद में जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए तब आप उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। कोई भी निर्णय लेते समय इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि भावावेश में आकर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अकसर गलत साबित होता है।

भावनात्मक परिपक्वता

जब इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह स्वतः भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। जीवन में सफलता और सच्ची खुशी हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान भावनात्मक रूप से कितना परिपक्व होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति कितना सचेत है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में आठ सम्यक सूत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनके माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित आचरण अपनाने की शिक्षा दी गई है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, तुम वीणा के तारों को इतना न कसो कि वे टूट जाएं और न ही इतना ढीला छोड़ों कि उनसे स्वर न निकले। कहने का अर्थ यह है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के मामले में हमेशा संतुलन होना चाहिए।

समझें दूसरों की भावनाएं

भावनात्मक रूप से संतुलित होने के लिए खुद को समझने के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों का सामाजिक व्यवहार हमेशा संतुलित होता है। दूसरों के व्यक्तित्व की खूबियों-खामियों को पहचानने और उनके मन की बातों को पढ़ पाने का गुर जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम आता है। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक। अगर आप दूसरों को समझते हैं तो यह आपके लिए भी अच्छा होगा। दूसरों की भावनाओं को बारीकी से समझ पाना भावनात्मक विवेक का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

मुश्किल का हल

दफ्तर में जो व्यक्ति अपने साथियों के व्यक्तित्व को समझने में सफल होता है, अगर कभी उसके सामने कोई मुश्किल आती है तो वह आसानी से उसका हल ढूंढ लेता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी भावनात्मक रूप से संतुलित लोग अपने सभी संबंधों का निर्वाह अच्छी तरह कर पाते हैं। वे अपने जीवनसाथी, दोस्तों और रिश्तेदारों के व्यवहार को ध्यान से देखते हुए उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक-नकारात्मक पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों के साथ उनका व्यवहार बेहद संयत होता है। उन्हें मालूम होता है कि अगर किसी से अपनी बात मनवानी भी है तो उसके सामने किस ढंग से पेश आना चाहिए। बच्चों की परवरिश के मामले में भावनात्मक संतुलन की भूमिका काफी अहम होती है।

व्यवहार कुशलता

समाज में लोगों के साथ व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी उसके भावनात्मक विवेक को आंका जाता है। भले ही किसी व्यक्ति से आपके वैचारिक मतभेद हों या किसी कारण से आप उसे नापसंद करते हों, लेकिन जब वह सामने मिले तो उसके साथ आपका व्यवहार हमेशा सहज और संतुलित होना चाहिए। जीवन के हर मोर्चे पर कामयाबी हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर आप सचेत ढंग से इन सुझावों पर अमल करेंगे तो आपके लिए भावनात्मक संतुलन स्थापित करना आसान हो जाएगा।

संतुलन के कुछ सरल नियम

- **इमोशन मैनेजमेंट डायरी:** अपने लिए एक इमोशन मैनेजमेंट डायरी बनाएं, रोजाना रात को सोने से पहले उसमें दर्ज करें कि पूरे दिन में आपने कितनी बार और किन स्थितियों में नकारात्मक व्यवहार किया, ताकि अगली बार वैसी स्थिति में आप अपने व्यवहार में सुधार ला सकें।
- **यह आदत डालें:** समस्याओं से दुखी होने के बजाय उन्हें हल करने की आदत डालें।घर और बाहर दोनों जगहों पर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बिगड़े हुए संबंध को सुधारने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखें और सहनशक्ति को मजबूत बनाएं।
- **भावुक क्षणों में फैसला न लें:** भावुक क्षणों में कोई भी निर्णय न लें क्योंकि इसमें अकसर गलतियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बढाएं, जिनसे बातें करके आपको खुशी मिलती है। अच्छे सामाजिक संबंध भावनात्मक संतुलन बनाने में मददगार होते हैं।
- **असफलताएं हैं जीवन का हिस्सा:** करियर के क्षेत्र में मिलने वाली छोटी-छोटी असफलताओं को पहले से ही अपने जीवन का जरूरी हिस्सा मानकर चलें। अपनी नाकामी से निराश होने के बजाय यह संकल्प लें कि दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप छात्र हैं या करियर बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं तो अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना सीखें।
- **अपनी क्षमताओं को जानें:** अपनी क्षमता के अनुरूप ही परिणाम की आशा रखें। अति महत्वाकांक्षा और उसके पूर्ण न होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने प्रोफेशन के संबंध में निरंतर नई जानकारियां हासिल करें और काम की नई तकनीकें सीखते रहें। इससे आप स्वयं को हमेशा युवा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
- **अपने ऊपर ध्यान दें:** अगर ऐसा लगता है कि वाकई आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ रहा है तो अपने ऊपर पूरा ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें, योगाभ्यास और ध्यान करें।परिवार के साथ पूरा समय बिताएं। छुटिटयों में कहीं घूमने जाएं। हमेशा अच्छा सोचें। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।

जानें किताब पढ़ने के फायदे...

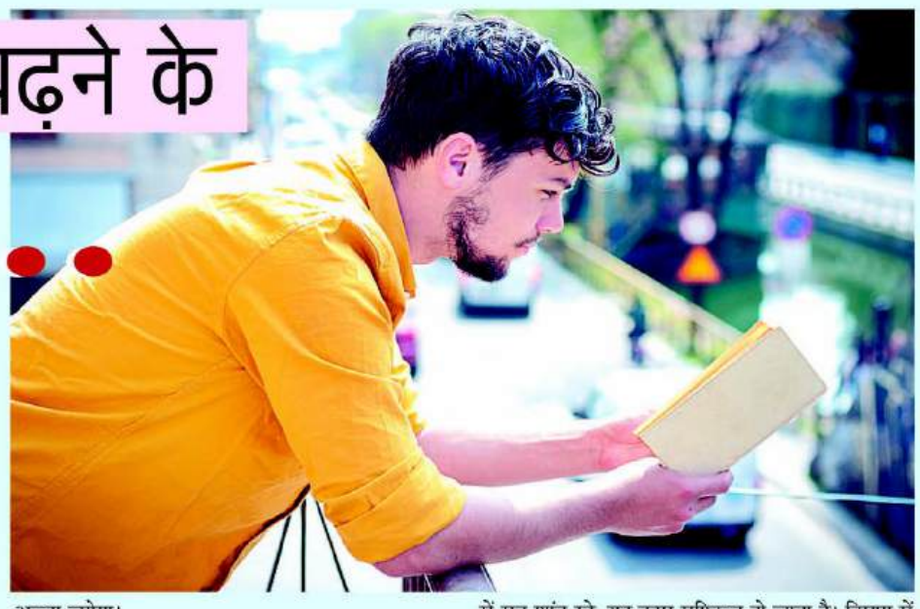

पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यदि आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग को एक शौक के रूप में लेने पर विचार करना चाहिए। अक्सर लोगों के पढ़ने के पीछे के प्रयोजनों में कोई काम या शौक होता है। लेकिन वास्तव में पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यदि आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग को एक शौक के रूप में लेने पर विचार करना चाहिए। हर दिन एक किताब के कुछ पन्नों को पढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसे शुरू करें या फिर समाचार देखने के बजाय अखबार पढ़ें। जल्द ही आपको अहसास होगा कि आप फिल्में देखने के बजाए किताबें पढ़ने की अच्छी आदत के मालिक हो चुके हैं।

तनाव कम होता है

किताब पढ़ना आपके तनाव को कम करता है, क्योंकि यह एक तरह की शांतिपूर्ण गतिविधि होती है। यह ऐसी गतिविधि नहीं है, जो आपके विचारों को उत्तेजित करे। हां, किताब पढ़ने के दौरान यह जरूर देखें कि आप किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं। याद रहे कि अवसाद और तनावग्रस्त होने पर हमेशा दिमाग को शांत करने वाली या फिर मन को हल्का करने वाली किताब ही पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा।

अकेलापन दूर होता है

किताब पढ़ने का एक फायदा यह है कि ये आपका अकेलापन दूर करती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किताब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। किताब तनाव से दूर ले जाती है और उन विचारों से दूर ले जाती है, जो आपको परेशान करते हैं।

फालतू बातों पर लगाम

किताब पढ़ने का एक फायदा यह है कि तनाव के दौरान तरह-तरह की फालतू बातें दिमाग में आती हैं। ऐसे में मन शांत रहे, यह काम मुश्किल हो जाता है। दिमाग में आई फालतू बातों पर लगाम लगाने का काम करती हैं किताबें। तनाव में किताब पढ़ने से दिमाग में मौजूद फालतू बातें बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि आप एकाग्रचित्त हो कर किताब पढ़ रहे होते हैं।

सोचने की क्षमता का विकास

पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपने शरीर को भी कष्ट नहीं पहुंचाना होता है। तनाव के दौरान यूं भी कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे में आप चुपचाप कहीं भी बैठ कर आराम से कोई किताब पढ़ सकते हैं। कई बार हम स्वकेंद्रित हो जाते हैं। कुछ नया नहीं सोच पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगते हैं, पर किताब पढ़ने के दौरान आपके सामने कई सारी ऐसी बातें होती हैं, जो आप पर केंद्रित नहीं होती हैं। ऐसे में एक तरह से आपकी अन्य बातों को सोचने की क्षमता का विकास ही होता है।

मस्तिष्क का व्यायाम

पढ़ना एक प्रकार बेहतर तरीके से मस्तिष्क को उद्दीस करना करता है, जोकि टीवी देखने या रेडियो सुनने से कभी नहीं हो सकता। फिर भले ही आप कोई नया थ्रिलर पढ़ रहे हों या फिर अपने डीवीडी प्लेयर का अनुदेश मैनुअल, पढ़ने से आपका मस्तिष्क संलग्न रहता है और उसकी एक्सरसाइज होती है।

याददाश्त बढ़ती है

जो लोगो पढ़ाई करते रहते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है। टीवी देखने और कंप्यूटर पर काम करने की तुलना में पढ़ाई करने वालों का दिमाग अधिक तेज होता है। इसके अलावा पढ़ने की आदत व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है।

दिमाग जवां रहता है

पढ़ने की आदत से इंसान का दिमाग हमेशा जवां रहता है। एक शोध के अनुसार, वे लोग जो रचनात्मक कामों जैसे पढ़ाई आदि में अधिक समय बिताते हैं, उनका दिमाग ऐसा न करने वाले लोगों की तुलना में 32 प्रतिशत तक अधिक युवा बना रहता है।

अल्जाइमर से बचाव

अल्जाइमर उम्रदराज लोगों में होने वाला एक मानसिक रोग है, जिसके कारण व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। जो दिमागी गतिविधियों जैसे, पढ़ाई, चेस खेलना, पजल हल करना आदि में व्यस्त रहते हैं।

फंकी लुक और पार्टी वेयर 'किमोनो' है ट्रैंड में

फैशन जगत में भी लुक ईस्ट पॉलिसी पर फोकस किया जा रहा है। जापानी गुड़िया पर सजने वाली चीजें अब दुनिया के हर कोने के साथ-साथ भारत में भी खासी पसंद की जा रही हैं। 'किमोनो' भी इनमें से एक है। जो बहुत ही ट्रेंडी हैं। इस ढीले-ढाले परिधान को किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना जा सकता है। इसे मॉडर्न आउटफिट कम टेड्रिशनल कहा जा रहा है। बॉलीवुड हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रहा है। दीपिका पादुकोण ने 'किमोनो' को भी काफी पापुलर बना दिया है। गल्सज़ अपने आप को डिफरेंट और अट्रैक्टिव दिखाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए यूनिक और स्टाइलिश 'किमोनो' टॉप्स में हैं। ये काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब गर्ल्स भी 'किमोनो' टॉप्स में नजर आ रही हैं जो की उन्हें अट्रैक्टिव लुक दे रहा। ये लुक टीनेजर्स को बहुत लुभा रहा है। 'किमोनो' टॉप्स कलरफूल और सिम्पल लुक में भा रहे हैं। प्लेन और प्रिंटेड 'किमोनो' को जींस या पैंट्स के ऊपर पहन सकते हैं।

स्टाइलिश क्रेप व 'किमोनो' चलन में

कैजुअल लुक, फंकी लुक और पार्टी वेयर लुक के अलावा स्टाइलिश क्रेप और 'किमोनो' काफी चलन में है। नेट 'किमोनो' भी प्रचलित में है। मिनी स्कर्ट या शॉर्ट्स, फुल स्किनी ट्राउजर के साथ इसे कैरी कर सकते हैं और इसमें अटैच बेल्ट से इसे कमर में टाइट कर सकते हैं। ये बैक साइड से पूरा कवर होता है और सामने से हाफ ओपन होता है ताकि अंदर जो जीन्स और स्कर्ट पहना है वो नजर आ सके। ये गर्ल्स को स्टाइलिश लुक दे। जापानी 'किमोनो' का डिजाइनर आउटफिट्स काफी लड़कियों को लुभा रहा है जो स्लीवलेस कुर्ती और टी सर्ट के साथ कैरी किया जा रहा है।

फॉलो कर रही हैं

इस सीजन में सबसे ज्यादा चलन में है तो वो है 'किमोनो'। गर्ल्स ये ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। यही नहीं इसमें भी नए-नए इन्नोवेशन देखने को मिल रहे हैं।

इसे जींस के साथ कैरी किया जा सकता है तो वहीं प्लाजो के साथ भी इसे पहना जा सकता है। कैजुअल लुक, फंकी लुक और पार्टी वेयर लुक के लिए भी इसे ट्राय कर सकते हैं। ये नया ट्रेंड है और कूल भी है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**